गरवी गुजरात

PRGI No. GUJHIN/2011/39228

गरवी गुजरात

PUBLISHED HINDI DAILY FROM AHMEDABAD

वर्ष : 16
अंक : 050
दि. 19.06.2026,
शुक्रवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

राष्ट्र प्रथम की नीति

गुजरात सरकार

नक्सलमुक्त भारत का सपना साकार, आतंकवाद पर हो रहा कड़ा प्रहार

गुलामी की मानसिकता से मुक्ति, राजपथ बना कर्तव्य पथ,

छत्रपति शिवाजी महाराज की राजमुद्रा से प्रेरित नौसेना का नया ध्वज

12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के

आतंकवाद के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस नीति और नक्सलमुक्त भारत की दिशा में उठाए गए ऐतिहासिक कदमों से हमारी सरकार ने 'राष्ट्र प्रथम' के संकल्प को अडिग बनाए रखा है।

- श्री हर्ष संघवी, माननीय उपमुख्यमंत्री, गुजरात

हाईकोर्ट के फैसले से बंगाल की राजनीति में हलचल, ममता खेमे को बड़ा झटका, ऋतब्रत बनर्जी बने रहेंगे नेता प्रतिपक्ष

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजनीति में चल रहे अभूतपूर्व सत्ता संघर्ष के बीच कलकत्ता हाईकोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले ने राज्य के राजनीतिक समीकरणों को और अधिक गर्म कर दिया है। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के भीतर उभरे बगावत के संकट के बीच अदालत ने फिलहाल विधानसभा स्पीकर के उस निर्णय पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, जिसके तहत बागी नेता ऋतब्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता दी गई थी। अदालत के इस रुख को ममता बनर्जी खेमे के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि अंतिम फैसला आने तक ऋतब्रत बनर्जी विपक्ष के नेता के पद पर बने रहेंगे।

कलकत्ता हाईकोर्ट की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि प्रथम दृष्टया ऐसा कोई आधार नहीं दिखाई देता, जिसके आधार पर तत्काल अंतरिम राहत दी जा सके। अदालत ने दोनों पक्षों को अपने-अपने हलफनामे दाखिल करने का निर्देश देते हुए मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए अगली तारीख निर्धारित कर दी है। न्यायालय के इस आदेश का सीधा अर्थ यह है कि विधानसभा स्पीकर द्वारा दिया गया फैसला फिलहाल प्रभावी रहेगा और ऋतब्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मिली मान्यता बरकरार रहेगी।

यह मामला केवल एक संवैधानिक विवाद नहीं है, बल्कि पश्चिम बंगाल की सियासत में पिछले कई सप्ताह से चल रहे बड़े राजनीतिक भूचाल का परिणाम है। राज्य में विधानसभा चुनावों के बाद तृणमूल कांग्रेस के भीतर असंतोष की खबरें लगातार सामने आ रही थीं। इसी बीच पार्टी से निष्कासित किए जा चुके ऋतब्रत बनर्जी ने दावा किया कि उनके साथ बड़ी संख्या में विधायक खड़े हैं और वे विधानसभा में वास्तविक विपक्षी ताकत का प्रतिनिधित्व करते हैं। बाद में उन्होंने अपने समर्थन में दर्जनों विधायकों के हस्ताक्षर होने का दावा भी किया। विभिन्न रिपोर्टों में यह संख्या 58 से लेकर 64 विधायकों तक बताई गई है।

राजनीतिक संकट तब और गहरा गया जब ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट ने स्वयं को तृणमूल कांग्रेस के भीतर एक अलग विधायी समूह के रूप में पेश करना शुरू कर दिया। दिलचस्प बात यह रही कि इस गुट ने ममता बनर्जी के प्रति सम्मान व्यक्त किया, लेकिन पार्टी के संगठनात्मक ढांचे और विशेष रूप से अभिषेक बनर्जी की भूमिका को लेकर खुली असहमति जताई। इससे यह स्पष्ट संकेत मिला कि विवाद केवल विपक्ष के नेता के पद तक सीमित नहीं है, बल्कि पार्टी के नेतृत्व और भविष्य की दिशा को लेकर भी गंभीर मतभेद मौजूद हैं।

इसी राजनीतिक खींचतान के बीच विधानसभा स्पीकर रथेंद्र बोस के समक्ष दोनों पक्षों ने अपना-अपना दावा पेश किया। स्पीकर ने उपलब्ध दस्तावेजों और विधायकों के समर्थन के आधार पर ऋतब्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता दे दी। इस निर्णय ने राज्य की राजनीति में नया मोड़ ला दिया। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले आधिकारिक टीएमसी खेमे ने इसे पूरी तरह अस्वीकार करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया।

याचिका में तर्क दिया गया कि किसी भी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के चयन का अधिकार संबंधित राजनीतिक दल को होना चाहिए, न कि किसी बागी समूह को। ममता खेमे की ओर से अदालत में यह भी कहा गया कि स्पीकर का निर्णय संवैधानिक व्यवस्था और संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है। याचिकाकर्ताओं का दावा था कि पार्टी द्वारा आधिकारिक रूप से नामित नेता की अनदेखी कर किसी निष्कासित विधायक को नेता प्रतिपक्ष बनाना लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है।

सुनवाई के दौरान अदालत ने इस संवैधानिक प्रश्न पर भी चर्चा की कि क्या विधानसभा स्पीकर किसी राजनीतिक दल द्वारा प्रस्तावित नाम को नजरअंदाज कर किसी अन्य विधायक को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता दे सकता है। हालांकि अदालत ने इस विषय पर अंतिम राय व्यक्त नहीं की, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए विस्तृत सुनवाई जारी रखने का फैसला किया।

हाईकोर्ट के ताजा फैसले के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मामला केवल नेता प्रतिपक्ष के पद तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि तृणमूल कांग्रेस के भीतर शक्ति संतुलन और संगठनात्मक नियंत्रण की लड़ाई को भी प्रभावित करेगा। यदि बागी गुट अपना समर्थन बनाए रखने में सफल रहता है, तो आने वाले समय में राज्य की राजनीति में और बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

ममता बनर्जी के लिए यह स्थिति इसलिए भी चुनौतीपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि लंबे समय बाद उनकी पार्टी को अंदरूनी स्तर पर इतने बड़े विद्रोह का सामना करना पड़ रहा है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी का प्रभाव निर्विवाद रहा है, लेकिन मौजूदा घटनाक्रम यह संकेत दे रहा है कि पार्टी के भीतर नेतृत्व और रणनीति को लेकर असहमति खुलकर सामने आ चुकी है। दूसरी ओर ऋतब्रत बनर्जी लगातार यह दावा कर रहे हैं कि उनके पास बड़ी संख्या में विधायकों का समर्थन है और वे विधानसभा में वास्तविक विपक्ष की आवाज हैं।

फिलहाल अदालत द्वारा अंतरिम राहत देने से इनकार किए जाने के बाद ऋतब्रत बनर्जी की स्थिति मजबूत दिखाई दे रही है। हालांकि अंतिम फैसला अभी आना बाकी है और अदालत में संवैधानिक तथा कानूनी बहस आगे भी जारी रहेगी। अगली सुनवाई में दोनों पक्ष अपने विस्तृत तर्क और दस्तावेज पेश करेंगे, जिसके बाद यह स्पष्ट हो सकेगा कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद को लेकर चल रही यह लड़ाई किस दिशा में आगे बढ़ती है।

पतंजलि स्टोर पर एक्सपायर्ड अचार बेचने और बिल का भुगतान न करने पर 50,000 का जुर्माना लगाया गया, ग्राहक को न्याय मिला

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। अदालत ने पतंजलि स्टोर्स और कंपनी के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए एक जागरूक ग्राहक पर एक्सपायरी डेट के बाद भी बिल दिए बिना खाद्य सामग्री बेचने के लिए 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार, वडागम निवासी और जागरूक ग्राहक राहुलभाई प्रजापति ने 23/04/2024 को मोडासा स्थित "सर्वोदय चिकित्सालय पतंजलि स्टोर्स" से पतंजलि कंपनी का "हिमालय चेरी पेपर अचार" निर्धारित राशि का भुगतान करके खरीदा था। खरीदारी के बाद, राहुलभाई ने नियमों के अनुसार दुकानदार से वैध बिल मांगा था, लेकिन दुकानदार ने बिल देने से साफ इनकार कर दिया।

जब ग्राहक ने अचार की बोतल पर लिखी जानकारी देखी, तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई कि उत्पाद की एक्सपायरी डेट 24/01/2024 को निकल चुकी थी, यानी खरीद से तीन महीने पहले। ग्राहक ने स्टोर मैनेजर से बिल और एक्सपायरी डेट दिखाने का विनम्र अनुरोध किया, लेकिन स्टोर ने उनकी बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। स्टोर मालिक के इस रवैये से नाराज होकर ग्राहक राहुलभाई ने अरावली जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद के कार्यालय में इस संबंध में लिखित शिकायत दर्ज कराई। संगठन के प्रतिनिधि सिराज मंसूरी ने इस मामले में पतंजलि स्टोर को एक आधिकारिक नोटिस भेजा। लेकिन पतंजलि की ओर से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला।

उपभोक्ता हित में, अरावली जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में पतंजलि स्टोर्स (मोदासा) और निर्माता पतंजलि कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। अरावली जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष एम. एच. पटेल और सदस्य एस. पी. श्रीमाली की जूरी के समक्ष मामला लंबित था, जहां मोडासा स्थित पतंजलि स्टोर के खिलाफ कड़ा फैसला सुनाया गया।

इस मामले में आयोग ने अनैतिक व्यापारिक प्रथाओं के लिए पतंजलि पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है और उसे यह राशि गांधीनगर के "उपभोक्ता कल्याण कोष" में जमा करने का आदेश दिया है। आयोग ने शिकायतकर्ता ग्राहक राहुलभाई प्रजापति को मामला दर्ज करने की तारीख से 7% ब्याज सहित वस्तु की पूरी कीमत लौटाने और मानसिक पीड़ा और कानूनी खर्चों के लिए अलग से 4,000 रुपये का भुगतान करने का भी आदेश दिया है। यह अनुचित व्यवहार करने वाले व्यापारियों के लिए एक कड़ा संदेश है।

इस ऐतिहासिक निर्णय से उपभोक्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई है, जबकि अवैध रूप से एक्सपायर्ड सामान बेचने वालों या बिलों का भुगतान न करने वालों में असंतोष फैल गया है।

AAP विधायक चैतर वसावा की उपस्थिति में सागबारा तालुका के खोपी में जनकल्याण शिविर और वृक्षारोपण कार्यक्रम का सफल आयोजन

- जनकल्याण शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों को मिले सरकारी योजनाओं के लाभ
- जनकल्याण शिविर के माध्यम से अंतिम छोर के गांवों तक योजनाएं पहुंचाने का प्रयास : चैतर वसावा
- किसी भी क्षेत्र का विकास केवल निर्वाचित प्रतिनिधियों या अधिकारियों के प्रयासों से संभव नहीं है, बल्कि अधिकारियों, पदाधिकारियों और जनता के सामूहिक प्रयासों से ही विकास की गति को बढ़ावा मिल सकता है : चैतर वसावा
- शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक विकास जैसे क्षेत्रों में सभी के सहयोग से क्षेत्र को अधिक प्रगतिशील बनाया जा सकता है :

अहमदाबाद/नर्मदा/गुजरातः आज नर्मदा जिले के सागबारा तालुका के खोपी में जनकल्याण शिविर तथा वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जनता की विभिन्न लंबित समस्याओं का समाधान करना तथा सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम छोर के गांवों तक पहुंचाना था। इस कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी के डेडियापाड़ा विधानसभा क्षेत्र के विधायक चैतर वसावा, नर्मदा जिला पंचायत की कार्यकारी समिति की अध्यक्ष अस्मिताबेन आजादसिंह ठाकोर, नर्मदा जिला पंचायत की स्वास्थ्य समिति के चेयरमैन डॉ. दयाराम वसावा, सागबारा तालुका पंचायत के प्रमुख जगदीशभाई वसावा, तालुका पंचायत के कार्यकारी अध्यक्ष जयंतभाई वसावा, तालुका पंचायत न्याय समिति की अध्यक्ष प्रियंकाबेन वसावा, खोपी जिला पंचायत के सदस्य गिरधनभाई वसावा, सागबारा जिला पंचायत की सदस्य हेतलबेन चेतनभाई तड़वी, पांचपीपरी तालुका पंचायत की सदस्य अनिताबेन कोठारी, नरवाड़ी तालुका पंचायत की सदस्य सुमनबेन तड़वी, बरकतुरा तालुका पंचायत की सदस्य भावतीबेन वसावा, देवसाकी तालुका पंचायत की सदस्य आर्तिकाबेन वसावा, उभारिया तालुका पंचायत की सदस्य अंजुबेन वसावा, नाल तालुका पंचायत की सदस्य वीणाबेन वसावा तथा सिमआमली तालुका पंचायत के सदस्य चमारियाभाई वसावा सहित प्रशासनिक तंत्र के अधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।

इस अवसर पर विधायक चैतर वसावा ने कहा कि सरकार की विभिन्न विकासोन्मुख और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए जनकल्याण शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर में विभिन्न विभागों के अधिकारियों द्वारा लोगों को योजनाओं के बारे में मार्गदर्शन दिया गया तथा स्थल पर ही अनेक सेवाएं और लाभ प्रदान किए गए। उन्होंने आगे कहा कि किसी भी क्षेत्र का विकास केवल निर्वाचित प्रतिनिधियों या अधिकारियों के प्रयासों से संभव नहीं है, बल्कि अधिकारियों, पदाधिकारियों और जनता के सामूहिक प्रयासों से ही विकास की गति को बढ़ावा मिल सकता है। शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक विकास जैसे क्षेत्रों में सभी के सहयोग से क्षेत्र को अधिक प्रगतिशील बनाया जा सकता है। कार्यक्रम के दौरान तालुका विकास अधिकारी, मामलतदार तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी और लाभार्थी उपस्थित रहे। बड़ी संख्या में ग्रामीणों, सरपंचों, तालुका और जिला पंचायत के सदस्यों तथा अन्य अग्रणियों की उपस्थिति में कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। जनकल्याण शिविर में विभिन्न योजनाओं के संबंध में जानकारी, मार्गदर्शन और लाभ प्रदान किए गए, जिससे स्थानीय लोगों में उत्साह देखने को मिला। आयोजकों ने बताया कि सभी के सहयोग और संयुक्त प्रयासों से कार्यक्रम सफल रहा।

संपादकीय

सुरक्षित सिरप

भारत में छोटे-मोटे रोगों के उपचार के लिये मेडिकल स्टोर से दवा लेकर खाने की लोगों में आदत पायी जाती है। यह जाने बगैर कि घरेलू नीम-हकीमी जान को खतरे में भी डाल सकती है। भारत तथा कई अन्य देशों में देश में बने सिरप के सेवन से बच्चों की मृत्यु से दवा उद्योग पर आंच आई थी। यही वजह है कि खांसी व अन्य दवाओं के सिरप की बिना डॉक्टर की पर्ची के बिक्री पर रोक लगाने का फैसला सरकार को लेना पड़ा है। निश्चय ही केंद्र सरकार द्वारा यह फैसला सही समय पर लिया गया जरूरी कदम कहा जा सकता है। निस्संदेह, सरकार के इस कदम को सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ी सुरक्षा को मजबूत करने की बड़ी कोशिश का हिस्सा माना जाना चाहिए। हाल की कुछ दुखद घटनाओं के घातक परिणामों के मद्देनजर लोगों को हर खांसी-जुकाम आदि छोटे-मोटे रोगों के लिये खुद दवा लेने की आदत से परहेज करना चाहिए। दरअसल, भारत में लंबे समय से ऐसी धारणा रही है कि ये सिरप आदि दवाइयां मौसमी बीमारियों के लिये नुकसान-रहित होती हैं। लेकिन पिछले कुछ समय में हुई दुखद घटनाओं ने इनके अंधाधुंध प्रयोग और दवा निर्माण से जुड़े कमजोर नियमन को ही उजागर किया है। सरकार को ये कदम अनेक दुखद घटनाओं के सामने आने के बाद उठाना पड़ा है, जब इन दवाओं के उत्पादन में गंभीर खामियां सामने आईं। कुछ समय पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आरोप लगाए गए थे कि गैम्बिया,उज्बेकिस्तान और कैमरून आदि देशों में दर्जनों बच्चों की मौत भारत में बने दूषित खांसी के सिरप के उपयोग से हुई थी। इतना ही नहीं, देश के भीतर भी दूषित दवाओं से जुड़ी मौतों की खबरों ने इन सिरपों की गुणवत्ता नियमन, परीक्षण और निगरानी पर गाहे-बगाहे सवाल उठाए हैं। निश्चित रूप से इन दुखद घटनाओं ने दुनिया भर में सस्ती दवाओं की आपूर्ति करने वाले भारत की प्रतिष्ठा को नुकसान ही पहुंचाया है। सरकार की हालिया पहल को इसी दिशा में उठाया गए कदम के रूप में देखना चाहिए।

लेकिन सवाल सिर्फ कफ सिरप का ही नहीं है। आम भारतीयों की आदत में शुमार है कि लोग अक्सर खांसी-बुखार की दवाइयां यह जाने बगैर सेवन करते हैं कि उनमें क्या-क्या मिला है। यह भी कि इनके उपयोग से हमारे शरीर में क्या-क्या साइड-इफेक्ट हो सकते हैं। यह भी जानने की कोशिश नहीं होती है कि इन सिरप आदि को अन्य दवाओं के साथ लेने से क्या-क्या नकारात्मक प्रतिक्रिया हमारे शरीर में हो सकती है। बहरहाल, अब जब सरकार ने तय कर दिया है कि अनुभवी डॉक्टर की सलाह से ही सिरप आदि खरीदे जा सकते हैं तो मरीजों के तिमारदार तय कर सकेंगे कि किस कंपनी की गुणवत्ता वाली दवा खरीदनी है। जिससे न केवल इलाज सही हो सकेगा बल्कि यह भी सुनिश्चित हो सकेगा कि मरीज के शरीर में कोई अन्य बीमारी छूट न जाए। लेकिन हकीकत यह भी है कि सिर्फ कठोर कानून बनाने मात्र से ही बेहतर परिणाम हासिल नहीं किए जा सकते हैं। भारत में पहले से ही दवाइयों की बिक्री के नियमन से जुड़े कानूनों की कमी नहीं है। इसके बावजूद डॉक्टर की पर्ची पर ही उपलब्ध होने वाली दवाइयां अक्सर बिना पर्याप्त जांच-पड़ताल के ही आसानी से मेडिकल स्टोरों में मिल जाया करती हैं। दरअसल, असली चुनौती कानून का अनुपालन सख्ती से करने की होती है। जब तक देश में तमाम फार्मेसियों की नियमित जांच नहीं होती, कानून का उल्लंघन करने पर कड़े दंड का प्रावधान नहीं होता, तब नये नियम-कानून महज अच्छे इरादे वाले निर्देश मात्र बनकर रह जाएंगे। ऐसे में इस प्रयास का जमीनी असर बेहद कम ही रह पायेगा। वास्तव में देश में दवा उत्पादक इकाइयों की नियमित निगरानी, राज्यों में सशक्त ड्रग-कंट्रोल अथॉरिटी, नियमित गुणवत्ता जांच के अलावा जन चेतना अभियान चलाने की सख्त जरूरत है। लोगों को बिना डॉक्टर के परामर्श के दवा लेने के खतरों से अवगत कराना होगा। निस्संदेह, सरकार द्वारा चिकित्सक के परामर्श पर ही सिरप आदि की उपलब्धता से जुड़े नियम की कामयाबी इस बात पर निर्भर करेगी कि हम किस सीमा तक एक जवाबदेह सिस्टम बना पाते हैं।

विश्व शांति एवं संतुलन के लिए आत्ममंथन हो जी-7 बैठक में

> "जी-7 में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा और जापान शामिल हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से इसकी दिशा और नीति निर्धारण पर अमेरिका का प्रभाव सबसे अधिक दिखाई देता है। विशेष रूप से राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका की विदेश नीति ने सहयोग के बजाय दबाव और वर्चस्व की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया है।

फ्रांस में आयोजित जी-7 शिखर सम्मेलन पर इस समय पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था, अंतरराष्ट्रीय राजनीति, व्यापार, जलवायु परिवर्तन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऊर्जा सुरक्षा और युद्ध जैसे अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा के लिए दुनिया की सात प्रमुख विकसित अर्थव्यवस्थाओं का यह मंच एकत्रित हुआ है। ऐसे समय में यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि क्या जी-7 आज भी उतना ही प्रासंगिक और प्रभावशाली है, जितना उसकी स्थापना के समय था? क्या यह संगठन वास्तव में वैश्विक समस्याओं के समाधान का मंच बन पाया है अथवा यह कुछ शक्तिशाली देशों के हितों की रक्षा का माध्यम बनकर रह गया है? क्या इस मंच की प्रासंगिकता एवं उपयोगिता को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने स्वार्थों के चलते धुंधलाने में लगे हैं? विश्व में शांति स्थापना, संतुलित आर्थिक विकास और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बने विभिन्न वैश्विक संगठनों की सफलता का मूल्यांकन उनके परिणामों से होता है, न कि उनके घोषणापत्रों से। दुर्भाग्य से जी-7 के संदर्भ में यह प्रश्न बार-बार उठता रहा है कि उसके निर्णयों और घोषणाओं का वास्तविक प्रभाव कितना है। पिछले वर्षों में रूस-यूक्रेन युद्ध, पश्चिम एशिया का संकट, वैश्विक आर्थिक अस्थिरता, जलवायु परिवर्तन की चुनौती और बढ़ती व्यापारिक प्रतिस्पर्धा जैसी समस्याओं के समाधान में यह संगठन अपेक्षित भूमिका निभाने में सफल नहीं दिखा है। जी-7 में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा और जापान शामिल हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से इसकी दिशा और नीति निर्धारण पर अमेरिका का प्रभाव सबसे अधिक दिखाई देता है। विशेष रूप से राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका की विदेश नीति ने सहयोग के बजाय दबाव और वर्चस्व की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया है। ट्रंप ने अपने सहयोगी देशों के साथ भी कई बार ऐसा व्यवहार किया है, मानो वे साझेदार नहीं बल्कि अमेरिकी नीतियों का अनुसरण करने वाले अनुयायी हों। टैरिफ युद्ध, व्यापारिक प्रतिबंध, रक्षा व्यय को लेकर दबाव और

अनेक एकतरफा निर्णयों ने सदस्य देशों के बीच अविश्वास बढ़ाया है। विशेषतः ईरान- इजरायल युद्ध ने समूची दुनिया की अर्थव्यवस्था का धराशायी कर दिया और यह अब अमेरिका के कारण ही हुआ है क्योंकि पिछले कुछ महीनों में हिंसक संघर्ष ने पूरे क्षेत्र को एक व्यापक युद्ध की आशंका से भर दिया था। ईरान, इजरायल और इस क्षेत्र के अनेक गैर-राज्यीय समूह आमने-सामने खड़े दिखाई दे रहे थे। इस संघर्ष का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र होर्मुज जलमार्ग बन गया था, जहां से विश्व के लगभग पांचवें हिस्से का तेल गुजरता है। जी-7 समूह के देश भी इसको लेकर बंटे हुए थे।

यही कारण है कि जी-7 के भीतर आज पहले जैसी एकजुटता दिखाई नहीं देती। फ्रांस, जर्मनी, कनाडा और जापान जैसे देश कई मुद्दों पर अमेरिका से अलग दृष्टिकोण रखते हैं। ईरान युद्ध ही नहीं, बल्कि जलवायु परिवर्तन के प्रश्न पर, वैश्विक व्यापार के नियमों पर और बहुपक्षीय संस्थाओं की भूमिका को लेकर भी मतभेद सामने आते रहे हैं। ऐसे में यह अपेक्षा करना कठिन है कि यह संगठन विश्व की जटिल समस्याओं के समाधान के लिए कोई सर्वमान्य और प्रभावी रणनीति प्रस्तुत कर पाएगा। इस सम्मेलन में भारत की उपस्थिति विशेष महत्व रखती है। भारत भले ही जी-7 का सदस्य न हो, लेकिन उसकी बढ़ती आर्थिक शक्ति, वैश्विक प्रतिष्ठा और विकासशील देशों के प्रतिनिधि स्वरूप ने उसे इस मंच का एक महत्वपूर्ण सहभागी बना दिया है। यह अवसर केवल भारत की उपलब्धियों को प्रस्तुत करने का नहीं, बल्कि उन विकासशील और निर्धन देशों की आकांक्षाओं को मुखर करने का भी है, जिनकी आवाज अक्सर वैश्विक निर्णय प्रक्रिया में दब जाती है।

आज अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के अनेक देश आर्थिक संकट, खाद्य असुरक्षा, जलवायु आपदाओं और ऋण के बोझ से जूझ रहे हैं। उनकी प्राथमिकताएं जी-7 देशों की प्राथमिकताओं से भिन्न हैं। इसलिए भारत को यह प्रश्न उठाना चाहिए कि क्या विश्व की दिशा तय करने का अधिकार केवल कुछ विकसित देशों तक सीमित रहना चाहिए? क्या वैश्विक शासन व्यवस्था को अधिक लोकतांत्रिक, समावेशी और प्रतिनिधिक नहीं बनाया जाना चाहिए? यह समय विकासशील देशों की आवाज को मजबूती देने और वैश्विक दक्षिण (ग्लोबल साउथ) की चिंताओं को केंद्र में लाने का है। जी-7 की प्रासंगिकता पर सबसे बड़ा प्रश्न उसकी प्रभावशीलता को लेकर है। यदि कोई संगठन विश्व की प्रमुख समस्याओं को रोकने या सुलझाने में सक्षम नहीं है, तो उसकी उपयोगिता स्वतः प्रश्नों के घेरे में आ जाती है। रूस-यूक्रेन युद्ध वर्षों से जारी है। पश्चिम एशिया लगातार अशांत बना हुआ है। आतंकवाद और कट्टरता की चुनौतियां बनी हुई हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण पूरी दुनिया अभूतपूर्व संकटों का सामना कर रही है। इसके बावजूद वैश्विक नेतृत्व देने का दावा करने वाले मंचों की उपलब्धियां सीमित दिखाई देती हैं।

हाल के दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने तथा शांति और सहमति की दिशा में बढ़ने की खबरों ने पूरी दुनिया को राहत दी है। लंबे समय से चल रहे तनाव के कारण पश्चिम एशिया में अस्थिरता बढ़ रही थी और इसका प्रभाव वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा था। जैसे ही दोनों देशों के बीच समझौते और संवाद की संभावनाएं मजबूत हुईं, दुनिया भर के वित्तीय बाजारों में सकारात्मक संकेत दिखाई दिए। निवेशकों का विश्वास बढ़ा, ऊर्जा बाजार में स्थिरता के संकेत मिले और तेल की कीमतों में नरमी आई। इससे स्पष्ट है कि शांति केवल राजनीतिक उपलब्धि नहीं होती, बल्कि उसका सीधा संबंध वैश्विक आर्थिक स्थिरता और आम नागरिक के जीवन से भी होता है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है। यदि संवाद और समझौता ही अंततः समाधान का मार्ग था, तो फिर टकराव और तनाव की स्थिति को इतना लंबा क्यों खींचा गया? आखिर राष्ट्रपति ट्रंप को समझौते और सहमति के लिए राजी होने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? क्या इसके पीछे आर्थिक दबाव थे? क्या वैश्विक बाजारों की चिंता थी? क्या अमेरिकी जनता की अपेक्षाएं थीं? या फिर यह स्वीकारोक्ति थी कि युद्ध और दबाव की राजनीति की भी सीमाएं होती हैं? ये ऐसे प्रश्न हैं जिन पर जी-7 जैसे मंचों में गंभीर चर्चा होनी चाहिए।

विश्व समुदाय केवल औपचारिक शांति समझौतों से संतुष्ट नहीं हो सकता। आवश्यकता इस बात की है कि शांति स्थायी, विश्वसनीय और न्यायपूर्ण हो। यदि समझौते केवल राजनीतिक छवि निर्माण, चुनावी लाभ या अस्थायी रणनीतिक उद्देश्यों के लिए किए जाते हैं, तो वे लंबे समय तक टिक नहीं पाते। जी-7 को यह सुनिश्चित करने की दिशा में पहल करनी चाहिए कि विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले शांति प्रयास वास्तविक हों और उनका उद्देश्य मानवता के हितों की रक्षा करना हो। आज वैश्विक व्यवस्था एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ी है। दुनिया अब एकध्रुवीय नहीं रही। भारत, चीन, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक शक्ति संतुलन को नया स्वरूप दे रही हैं। ऐसे समय में जी-7 को भी अपनी कार्यशैली और दृष्टिकोण में परिवर्तन करना होगा। यदि यह मंच केवल अमेरिकी नेतृत्व और पश्चिमी हितों का प्रतिनिधि बना रहेगा, तो इसकी स्वीकार्यता और प्रभावशीलता लगातार घटती जाएगी।

आवश्यकता इस बात की है कि जी-7 स्वयं को अधिक समावेशी बनाए, विकासशील देशों को निर्णय प्रक्रिया में अधिक स्थान दे, आर्थिक न्याय और जलवायु न्याय के प्रश्नों पर ठोस पहल करे तथा वैश्विक शांति को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करे। अमेरिका को भी यह समझना होगा कि नेतृत्व और प्रभुत्व में अंतर होता है। नेतृत्व विश्वास अर्जित करता है, जबकि प्रभुत्व विरोध को जन्म देता है। फ्रांस में हो रहा यह सम्मेलन केवल आर्थिक या राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा का मंच नहीं होना चाहिए, बल्कि यह आत्ममंथन का अवसर भी बनना चाहिए। जी-7 को यह विचार करना होगा कि बदलती दुनिया में उसकी भूमिका क्या है और वह किस प्रकार अधिक उपयोगी, प्रभावी और विश्वसनीय बन सकता है। यदि यह संगठन अपने भीतर बढ़ते मतभेदों को दूर कर, समानता और सहयोग की भावना के साथ आगे बढ़ता है, तभी वह विश्व समुदाय की अपेक्षाओं पर खरा उतर सकेगा। भारत को इस अवसर पर साहसपूर्वक यह संदेश देना चाहिए कि विश्व का भविष्य शक्ति-संतुलन, संवाद, सहयोग और समावेशिता में निहित है। किसी एक देश या समूह की प्रभुत्ववादी सोच से नहीं, बल्कि साझी जिम्मेदारी और साझा विकास की भावना से ही विश्व में स्थायी शांति, आर्थिक स्थिरता और मानव कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। यही इस समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है और यही जी-7 जैसे मंचों की वास्तविक कसौटी भी।

प्रेरणा

धैर्य की शक्ति: हार के बाद फिर उठ खड़े होने की कला

जीवन में सफलता पाने का सपना हर व्यक्ति देखता है। कोई महान लेखक बनना चाहता है, कोई सफल व्यापारी, कोई वैज्ञानिक, तो कोई समाज में सम्मानित स्थान प्राप्त करना चाहता है। लेकिन सफलता का मार्ग कभी सीधा और सरल नहीं होता। इस रास्ते में असफलताएँ आती हैं, कठिनाइयाँ आती हैं, निराशा के क्षण आते हैं और कभी-कभी तो ऐसा भी लगता है कि वर्षों की मेहनत एक ही पल में नष्ट हो गई है। ऐसे समय में जो व्यक्ति धैर्य बनाए रखता है और दोबारा प्रयास करने का साहस जुटाता है, वही अंततः अपने लक्ष्य तक पहुँचता है। इतिहास गवाह है कि दुनिया के अधिकांश महान लोगों ने अपनी सबसे बड़ी सफलताएँ तब प्राप्त कीं, जब वे जीवन की सबसे बड़ी निराशाओं से जूझ रहे थे।

प्रसिद्ध इतिहासकार और लेखक थॉमस कार्लाइल का जीवन इसका एक प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत करता है। वे कई वर्षों से फ्रांसीसी क्रांति के इतिहास पर आधारित अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक दी फ्रेंच रेवोल्युशन लिख रहे थे। इस पुस्तक को तैयार करने में उन्होंने अनगिनत घंटे शोध में लगाए, दुर्लभ दस्तावेजों का अध्ययन किया और अपनी पूरी ऊर्जा इस कार्य में समर्पित कर दी। वर्षों की अथक मेहनत के बाद जब पुस्तक का पहला मसौदा तैयार हुआ, तो उन्होंने उसे अपने एक मित्र को पढ़ने और सुझाव देने के लिए सौंप दिया। उन्हें विश्वास था कि अब उनका वर्षों का परिश्रम एक महान कृति के रूप में दुनिया के सामने आने वाला है।

लेकिन कभी-कभी जीवन हमारी योजनाओं के अनुसार नहीं चलता। कुछ दिनों बाद उनके मित्र ने अत्यंत दुखी होकर बताया कि घर की नौकरानी ने उन कागजों को बेकार समझ लिया और अधिकांश पांडुलिपि को आग में जला दिया। यह समाचार सुनते ही कार्लाइल के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस रचना को तैयार करने में उन्होंने वर्षों का समय लगाया था, वह कुछ ही क्षणों में राख बन चुकी थी। यह केवल कागजों का नष्ट होना नहीं था, बल्कि उनके सपनों, परिश्रम और उम्मीदों का भी टूट जाना था।

कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति वर्षों तक किसी लक्ष्य के लिए मेहनत करे और अचानक वह सब कुछ नष्ट हो जाए। ऐसी स्थिति में अधिकांश लोग शायद हार मान लेते, अपने भाग्य को कोसते और आगे बढ़ने की इच्छा खो देते। कार्लाइल भी कुछ समय तक गहरे अवसाद और निराशा में डूबे रहे। उन्हें लगने लगा कि अब सब कुछ समाप्त हो चुका है। बार-बार वही विचार उनके मन में आता कि इतनी बड़ी हानि की भरपाई कैसे हो सकती है। वे अपने आपको असहाय महसूस कर रहे थे।

एक दिन वे उदास मन से टहलने निकले। चलते-चलते उनकी नजर एक निर्माणाधीन दीवार पर काम कर रहे मजदूर पर पड़ी। वह मजदूर बड़ी एकाग्रता और धैर्य के साथ एक-एक ईंट जोड़ रहा था। वह जल्दबाजी नहीं कर रहा था। उसे यह चिंता नहीं थी कि पूरी दीवार कब बनेगी। वह केवल अपने सामने रखी हुई अगली ईंट को सही स्थान पर लगाने पर ध्यान दे रहा था। कार्लाइल कुछ देर तक उसे देखते रहे। तभी उनके मन में एक गहरा विचार उत्पन्न हुआ। उन्होंने सोचा कि यह विशाल दीवार भी एक-एक ईंट जोड़कर ही तैयार हो रही है। इसी प्रकार उनकी पुस्तक भी एक-एक पृष्ठ लिखकर बनी थी। यदि वे एक बार इसे लिख सकते थे, तो दूसरी बार भी लिख सकते थे। यह विचार उनके जीवन का निर्णायक मोड़ बन गया। उन्होंने अपनी निराशा को त्याग दिया और उसी क्षण एक नया संकल्प लिया। वे घर लौटे और फिर से लिखना शुरू कर दिया। अब उनके सामने पहले से भी कठिन चुनौती थी, क्योंकि उन्हें पूरी पुस्तक स्मृति, शोध और पुनः परिश्रम के आधार पर तैयार करनी थी। लेकिन इस बार उनके भीतर धैर्य और दृढ़ता की नई शक्ति जाग चुकी थी। वे प्रतिदिन थोड़ा-थोड़ा लिखते रहे, जैसे वह मजदूर एक-एक ईंट जोड़ता जा रहा था। महीनों की लगातार मेहनत के बाद पुस्तक पुनः तैयार हो गई।

जब यह पुस्तक प्रकाशित हुई, तो उसे व्यापक प्रशंसा मिली। इतिहासकारों और पाठकों ने उसे एक उत्कृष्ट कृति के रूप में स्वीकार किया। कार्लाइल को सम्मान और प्रसिद्धि मिली, लेकिन उससे भी अधिक मूल्यवान वह शिक्षा थी जो उन्होंने इस अनुभव से प्राप्त की। उन्होंने समझ लिया कि सफलता केवल प्रतिभा का परिणाम नहीं होती। प्रतिभा तो अनेक लोगों के पास होती है, लेकिन कठिन परिस्थितियों में टिके रहने का धैर्य और गिरकर दोबारा उठ खड़े होने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। यही गुण किसी व्यक्ति को असाधारण बनाते हैं।

यह कहानी केवल एक लेखक की नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति की कहानी है जो जीवन में किसी लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। विद्यार्थी परीक्षा में असफल हो सकता है, व्यापारी को नुकसान हो सकता है, खिलाड़ी प्रतियोगिता हार सकता है, किसान की फसल खराब हो सकती है या किसी कर्मचारी को अपने करियर में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन असफलता का अर्थ यह नहीं है कि यात्रा समाप्त हो गई। वास्तव में असफलता केवल यह संकेत देती है कि हमें एक नए दृष्टिकोण, नए उत्साह और नए प्रयास के साथ आगे बढ़ना है।

धैर्य का अर्थ केवल कठिनाइयों को सहन करना नहीं है। धैर्य का अर्थ है परिस्थितियाँ प्रतिकूल होने पर भी अपने लक्ष्य पर विश्वास बनाए रखना। जब परिणाम तुरंत नहीं मिलते, तब भी निरंतर प्रयास करते रहना ही सच्चा धैर्य है। प्रकृति हमें यही शिक्षा देती है। बीज बोने के तुरंत बाद वृक्ष नहीं बनता। उसे मिट्टी के भीतर समय बिताना पड़ता है, धीरे-धीरे अंकुरित होना पड़ता है और वर्षों तक बढ़ते रहना पड़ता है। तभी वह विशाल वृक्ष बनकर फल और छाया प्रदान करता है।

आज के समय में लोग त्वरित सफलता चाहते हैं। वे चाहते हैं कि प्रयास करते ही परिणाम मिल जाएँ। लेकिन वास्तविक जीवन में बड़ी उपलब्धियाँ समय, मेहनत और धैर्य की मांग करती हैं। जो लोग छोटी-छोटी असफलताओं से घबराकर पीछे हट जाते हैं, वे अपने सपनों को अधूरा छोड़ देते हैं। वहीं जो लोग हर बाधा को सीखने का अवसर मानते हैं, वे अंततः सफलता की ऊँचाइयों तक पहुँचते हैं। थॉमस कार्लाइल की कहानी हमें याद दिलाती है कि जीवन में कुछ भी स्थायी रूप से खोया नहीं होता, जब तक हमारे भीतर फिर से शुरुआत करने का साहस जीवित है। यदि हमारी मेहनत का परिणाम नष्ट हो जाए, यदि परिस्थितियाँ हमारे विरुद्ध हो जाएँ, तब भी हम नए सिरे से निर्माण कर सकते हैं। हर महान उपलब्धि एक छोटे कदम से शुरू होती है और हर नई शुरुआत एक दृढ़ निर्णय से जन्म लेती है। इसलिए जब भी जीवन में कठिनाइयाँ आएँ, निराश होने के बजाय उस मजदूर की तरह एक-एक ईंट जोड़ते रहने का संकल्प लेना चाहिए।

Wedding Season शुरू हो गया, Iran-US War खत्म हो गयी, क्या अब Gold Jewellery को खरीदना सही रहेगा?

पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से एक साल तक सोना नहीं खरीदने और सादगी अपनाने की अपील की थी। उनका तर्क था कि भारत दुनिया के सबसे बड़े सोना आयातक देशों में शामिल है और जब कच्चे तेल की कीमतें तथा वैश्विक तनाव दोनों बढ़ते हैं, तब सोने का आयात देश के विदेशी मुद्रा भंडार और चालू खाते के घाटे पर भारी दबाव डालता है। इसी चिंता को देखते हुए सरकार ने सोना और चांदी पर सीमा शुल्क छह प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया था। इस फैसले के बाद देश में सोने का आयात करीब 70 प्रतिशत घटकर 75 से 100 टन प्रति माह के स्तर से गिरकर केवल 25 से 30 टन रह गया। हम आपको बता दें कि भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोना उपभोक्ता है और देश के कुल आयात में सोने की हिस्सेदारी पांच प्रतिशत से अधिक है। सरकार का मानना है कि पश्चिम एशिया में अनिश्चितताओं के कारण आयात लागत और बढ़ सकती है, इसलिए विदेशी मुद्रा को कच्चे तेल, उर्वरक, औद्योगिक कच्चे माल और पूंजीगत वस्तुओं जैसे आवश्यक आयातों के लिए बचाना जरूरी है। यही वजह थी कि प्रधानमंत्री मोदी ने आभूषणों पर अत्यधिक खर्च से बचने और अनावश्यक सोना खरीद पर नियंत्रण की अपील की थी।

दरअसल, भारत में सोने के प्रति मोह सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। यहां सोने का महत्व केवल निवेश तक सीमित नहीं है। भारत में सोना सामाजिक प्रतिष्ठा, सुरक्षा और पारिवारिक परंपरा का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि हर वर्ष सैकड़ों टन सोना आयात किया जाता है। आर्थिक रिपोर्टों के अनुसार भारत ने पिछले वर्ष 800 टन से अधिक सोना आयात किया, जबकि घरेलू उत्पादन बेहद कम रहा। विशेषज्ञों का मानना है कि इतनी भारी निर्भरता भारतीय रुपये पर दबाव बढ़ाती है।

अब सवाल यह है कि यदि ईरान अमेरिका संघर्ष समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, तो क्या लोगों को फिर से सोना खरीदना शुरू कर देना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर सीधा नहीं है, क्योंकि सोने की कीमतें केवल युद्ध से तय नहीं होतीं। उनमें डॉलर की मजबूती, अमेरिकी ब्याज दरें, केंद्रीय बैंकों की खरीदारी, महंगाई और निवेशकों की मनोवृत्ति भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

हाल के सप्ताहों में देखने को मिला कि जैसे ही अमेरिका और ईरान के बीच अस्थायी समझौते तथा युद्धविराम की खबरें सामने आयीं, अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में नरमी आई। तेल कीमतों में गिरावट और डॉलर की मजबूती के कारण सोना दबाव में रहा। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की सख्त ब्याज दर नीति ने भी सोने की चमक कम की।

हालांकि दूसरी ओर कई वैश्विक निवेश बैंक अब भी लंबे समय के लिए सोने को मजबूत निवेश मान रहे हैं। जेपी मोर्गन का अनुमान है कि 2026 और 2027 में सोने की कीमतें और ऊपर जा सकती हैं, क्योंकि दुनिया भर के केंद्रीय बैंक लगातार अपने भंडार में सोना जोड़ रहे हैं। कई विश्लेषकों का कहना है कि युद्ध समाप्त होने के बाद सोने में तात्कालिक गिरावट संभव है, लेकिन लंबी अवधि में इसकी मांग बनी रह सकती है। मार्केटवाच की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि केवल युद्ध के आधार पर सोना खरीदना हमेशा लाभकारी रणनीति नहीं होती, क्योंकि कई बार युद्ध के दौरान भी सोना गिरा है। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि सोने को भावनात्मक निर्णय की बजाय संतुलित निवेश के रूप में देखना चाहिए।

उधर, भारत में इस समय शादी विवाह का मौसम शुरू हो चुका है। पारंपरिक रूप से यह वह समय होता है जब परिवार आभूषण खरीदने के लिए बाजार का रुख करते हैं। लेकिन इस बार स्थिति अलग है। एक ओर कीमतों में भारी उतार चढ़ाव है, दूसरी ओर वैश्विक हालात को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। यही कारण है कि आम उपभोक्ता दुविधा में है कि अभी खरीदारी करे या कुछ समय प्रतीक्षा करे।

ज्वेलरी उद्योग से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि जिन परिवारों को अगले कुछ महीनों में विवाह के लिए आभूषण की आवश्यकता है, उन्हें पूरी खरीदारी एक साथ करने की बजाय चरणबद्ध तरीके से करनी चाहिए। यदि कीमतों में गिरावट आती है तो औसत लागत कम हो सकती है। निवेश के नजरिये से भी विशेषज्ञ सलाह दे रहे हैं कि केवल भौतिक सोना खरीदने के बजाय डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ईटीएफ या सावरिन गोल्ड बांड जैसे विकल्पों पर भी विचार किया जा सकता है।

इसके अलावा, ज्वैलरी बाजार में ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कई बड़े-छोटे ज्वैलर्स पुराने सोने के आभूषणों के बदले नये आभूषण देने की विशेष योजनाएं भी चला रहे हैं। बाजार में अनिश्चितता और ऊंची कीमतों के कारण ग्राहक सीधे नयी खरीदारी से बच रहे हैं, इसलिए ज्वैलर्स एक्सचेंज आफर, कम मेकिंग चार्ज और अतिरिक्त छूट जैसी योजनाएं लेकर आए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि जिन परिवारों के पास पुराना सोना रखा हुआ है, वे इन योजनाओं का लाभ उठाकर अपेक्षाकृत कम खर्च में नये डिजाइन के आभूषण खरीद सकते हैं। कई कंपनियां पुराने गहनों के मूल्यांकन पर अतिरिक्त बोनस भी दे रही हैं, जिससे ग्राहकों को बाजार की ऊंची कीमतों के बावजूद राहत मिल रही है। शादी विवाह के मौजूदा मौसम में यह विकल्प खास तौर पर मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए उपयोगी माना जा रहा है, क्योंकि इससे एकमुश्त भारी नकद खर्च का दबाव कम हो सकता है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि भारत में महंगाई और कच्चे तेल की कीमतों का सीधा असर सोने पर पड़ता है। हाल की रिपोर्टों में बताया गया है कि ईरान संघर्ष के कारण थोक महंगाई में तेजी आई थी। यदि युद्ध वास्तव में समाप्त होता है और तेल कीमतें स्थिर रहती हैं, तो भारतीय बाजार में सोने की कीमतों पर दबाव कम हो सकता है। बहरहाल, यह कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी की अपील तत्काल आर्थिक दबाव को कम करने की कोशिश थी।

अभियान

पांडवों की पश्चाताप यात्रा से जन्मे पंचकेदार, जहां शिव आज भी देते हैं मोक्ष का आशीर्वाद

भारतीय संस्कृति में तीर्थयात्रा को केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं माना गया है, बल्कि इसे आत्मा की शुद्धि और ईश्वर से जुड़ने का माध्यम समझा जाता है। देशभर में असंख्य तीर्थस्थल हैं, लेकिन कुछ स्थान ऐसे हैं जिनका महत्व केवल धार्मिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक, ऐतिहासिक और पौराणिक दृष्टि से भी अत्यंत विशेष है। उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में स्थित पंचकेदार उन्हीं दिव्य तीर्थों में से एक है। बर्फ से ढके पर्वतों, गहरी घाटियों, कल-कल बहती नदियों और अलौकिक प्राकृतिक सौंदर्य के बीच बसे ये पांच शिवधाम हजारों वर्षों से श्रद्धा और आस्था के केंद्र बने हुए हैं। माना जाता है कि यहां स्वयं भगवान शिव के अंग प्रकट हुए थे और यही कारण है कि पंचकेदार की यात्रा को भगवान शिव तक पहुंचने का सबसे पवित्र मार्ग माना जाता है।

पंचकेदार की महिमा का उल्लेख अनेक पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। यह केवल पांच मंदिरों की श्रृंखला नहीं, बल्कि भगवान शिव और पांडवों से जुड़ी एक ऐसी अद्भुत कथा है जो धर्म, कर्म, पश्चाताप और मोक्ष के गहन रहस्यों को अपने भीतर समेटे हुए है। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों ने भले ही विजय प्राप्त कर ली थी, लेकिन उनके मन में शांति नहीं थी। युद्ध में अपने ही कुल, रिश्तेदारों, गुरुओं और मित्रों का वध देखकर वे भीतर से टूट चुके थे। धर्म की स्थापना के लिए लड़ा गया युद्ध उन्हें राजसिंहासन तो दे गया, लेकिन आत्मिक संतोष नहीं दे सका।

पांडव जानते थे कि युद्ध में हुई हिंसा का प्रायश्चित आवश्यक है। उन्होंने ऋषियों और मुनियों से मार्गदर्शन प्राप्त किया। तब उन्हें बताया गया कि यदि वे भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर लें, तो उनके पापों का शमन हो सकता है। भगवान शिव को करुणा और क्षमा का सागर माना जाता है। वे अपने भक्तों के अपराधों को क्षमा कर उन्हें नई दिशा प्रदान करते हैं। यही आशा लेकर पांडव भगवान शिव की खोज में निकल पड़े।

कथा के अनुसार भगवान शिव पांडवों से अप्रसन्न थे। वे यह नहीं चाहते थे कि पांडव इतनी आसानी से उनके दर्शन प्राप्त कर लें। इसलिए उन्होंने स्वयं को छिपाने का निर्णय लिया और हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए। पांडव भी उनके पीछे-पीछे निकल पड़े। अनेक कठिनाइयों, घने जंगलों, ऊंचे पर्वतों और दुर्गम मार्गों को पार करते हुए वे हिमालय की उन घाटियों तक पहुंच गए जहां भगवान शिव ने बैल का रूप धारण कर लिया था।

जब भीम ने उस असाधारण बैल को देखा, तो उन्हें संदेह हुआ कि यह कोई साधारण पशु नहीं है। उन्होंने विशाल रूप धारण कर उसे पकड़ने का प्रयास किया। तभी बैल धरती में समाने लगा। भीम ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तभी एक अद्भुत घटना घटी। बैल का शरीर पांच भागों में विभाजित हो गया और उसके विभिन्न अंग हिमालय के पांच अलग-अलग स्थानों पर प्रकट हुए। इन पांचों स्थानों को बाद में पंचकेदार के नाम से जाना गया।

इन पांच धामों में सबसे प्रमुख केदारनाथ है। यह वही स्थान है जहां भगवान शिव की पीठ प्रकट हुई थी। हिमालय की ऊंची चोटियों से घिरा यह मंदिर भारतीय आध्यात्मिक परंपरा का एक अनमोल रत्न माना जाता है। हजारों वर्षों से साधु-संत और श्रद्धालु यहां पहुंचकर भगवान शिव की आराधना करते आए हैं। केदारनाथ की यात्रा कठिन अवश्य है, लेकिन श्रद्धालुओं का विश्वास है कि यहां पहुंचने मात्र से मनुष्य के जीवन के अनेक दोष दूर हो जाते हैं। मंदिर के आसपास का वातावरण एक अलग ही दिव्यता का अनुभव कराता है। ऐसा लगता है मानो प्रकृति स्वयं यहां भगवान शिव का ध्यान कर रही हो। केदारनाथ के बाद तुंगनाथ का स्थान आता है, जहां भगवान शिव की भुजाएं प्रकट हुई थीं। समुद्र तल से अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर संसार का सबसे ऊंचा शिव मंदिर माना जाता है। यहां पहुंचने वाला प्रत्येक श्रद्धालु प्रकृति और अध्यात्म के अद्भुत संगम का अनुभव करता है। पर्वतों की गोद में स्थित यह मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं, बल्कि आत्मचिंतन और आत्मशुद्धि का केंद्र भी है। मान्यता है कि यहां भगवान शिव के दर्शन करने से मन की अशांति दूर होती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।

रुद्रनाथ पंचकेदार का तीसरा धाम है, जहां भगवान शिव का मुख प्रकट हुआ था। यह स्थान अत्यंत रहस्यमयी और आध्यात्मिक माना जाता है। यहां भगवान शिव की पूजा रुद्र स्वरूप में की जाती है। रुद्रनाथ का प्राकृतिक वातावरण इतना शांत और मनमोहक है कि यहां पहुंचकर व्यक्ति सांसारिक चिंताओं को भूल जाता है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि यहां की गई प्रार्थना सीधे भगवान शिव तक पहुंचती है और उनकी कृपा से व्यक्ति के जीवन की अनेक बाधाएं दूर हो जाती हैं।

मध्यमहेश्वर पंचकेदार का चौथा धाम है। यहां भगवान शिव की नाभि और उदर भाग प्रकट हुआ था। यह स्थान अपने आध्यात्मिक वातावरण और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। मध्यमहेश्वर पहुंचने वाले भक्तों को ऐसा अनुभव होता है मानो वे किसी दिव्य लोक में प्रवेश कर गए हों। यहां की नीरवता मन को गहरे स्तर पर शांति प्रदान करती है। धार्मिक मान्यता है कि यहां पूजा-अर्चना करने से व्यक्ति को मानसिक संतुलन, पारिवारिक सुख और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है।

कल्पेश्वर पंचकेदार का अंतिम धाम है, जहां भगवान शिव की जटाएं प्रकट हुई थीं। यह पंचकेदार का एकमात्र मंदिर है जिसके कपाट पूरे वर्ष खुले रहते हैं। उर्गम घाटी में स्थित यह मंदिर साधना और ध्यान के लिए अत्यंत उपयुक्त माना जाता है। यहां आने वाले भक्त भगवान शिव के तपस्वी स्वरूप का अनुभव करते हैं। कल्पेश्वर की विशेषता यह है कि यहां पहुंचकर व्यक्ति को प्रकृति और परमात्मा के बीच गहरे संबंध का अनुभव होता है।

पंचकेदार की यात्रा केवल भौतिक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने की प्रक्रिया नहीं है। यह एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा है जो व्यक्ति के भीतर छिपे अहंकार, क्रोध, मोह और नकारात्मकता को धीरे-धीरे समाप्त करती है। जब श्रद्धालु कठिन पर्वतीय मार्गों पर चलता है, तब उसे जीवन का वास्तविक अर्थ समझ में आने लगता है। ऊंचे पर्वत उसे धैर्य का पाठ पढ़ाते हैं, बहती नदियां निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं और हिमालय की नीरवता उसे आत्मचिंतन का अवसर प्रदान करती है।

पंचकेदार का एक गहरा दार्शनिक महत्व भी है। भगवान शिव के शरीर के पांच अंगों का पांच अलग-अलग स्थानों पर प्रकट होना यह संकेत देता है कि परमात्मा किसी एक स्थान या रूप में सीमित नहीं है। वह संपूर्ण सृष्टि में विद्यमान है। प्रकृति का प्रत्येक कण ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव कराता है। पंचकेदार की यात्रा मनुष्य को इस सत्य का बोध कराती है कि ईश्वर की खोज बाहर से अधिक भीतर करनी चाहिए।

हजारों वर्षों से संत-महात्मा पंचकेदार को तप और साधना की भूमि मानते आए हैं। अनेक योगियों ने यहां कठोर तपस्या की और आत्मज्ञान प्राप्त किया। आज भी जब कोई श्रद्धालु इन धामों की यात्रा करता है, तो उसे केवल धार्मिक संतोष ही नहीं मिलता, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा का भी अनुभव होता है। यही कारण है कि आधुनिक जीवन की भागदौड़ से परेशान लोग भी यहां पहुंचकर एक नई शांति का अनुभव करते हैं।

पंचकेदार की यात्रा हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में भूल होना स्वाभाविक है, लेकिन उन भूलों को स्वीकार कर सुधारने का प्रयास करना ही सच्चा धर्म है। पांडवों ने भी अपने कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव की शरण ली थी। यह कथा हमें बताती है कि चाहे व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली या सफल क्यों न हो, उसे अपने कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए।

आज जब भौतिकता और प्रतिस्पर्धा के युग में मनुष्य अपने भीतर की शांति खोता जा रहा है, तब पंचकेदार की परंपरा उसे आत्मा की ओर लौटने का मार्ग दिखाती है। यह यात्रा केवल पापों से मुक्ति का माध्यम नहीं, बल्कि आत्मबोध और आध्यात्मिक जागरण का भी मार्ग है। यहां पहुंचकर व्यक्ति समझता है कि जीवन की वास्तविक सफलता बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि मन की शांति और ईश्वर से जुड़ाव में है। हिमालय की गोद में बसे पंचकेदार आज भी उसी दिव्यता और रहस्य को संजोए हुए हैं, जिसने हजारों वर्षों से करोड़ों लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया है।

PRGI NO. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HARDIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmdabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

19 जून : विश्व सिकल सेल दिवस

गुजरात में सिकल सेल एनीमिया नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत 1.11 करोड़ से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग

▸▸ 2006 में सिकल सेल एनीमिया नियंत्रण कार्यक्रम शुरू करने वाला गुजरात देश का पहला राज्य

▸▸ सिकल सेल रोगियों के लिए राज्य सरकार की संवेदनशील पहल, रोगी सहायता योजनांतर्गत 18.15 करोड़ रुपए की सहायता

▸▸ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 2047 तक सिकल सेल उन्मूलन के संकल्प को साकार करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध

गांधीनगर : हर वर्ष 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस मनाया जाता है; जिसका उद्देश्य सिकल सेल एनीमिया रोग के विषय में जागरूकता बढ़ाना और पीड़ित लोगों को समय पर निदान, उपचार एवं सहायता उपलब्ध कराना है। सिकल सेल एनीमिया एक आनुवंशिक रक्त विकृति (जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर) है, जो मुख्यतः आदिवासी समुदाय में देखने को मिलती है। इस वर्ष सिकल सेल दिवस की थीम 'क्लोजिंग द सर्वाइवल गैप : इक्विटी इन सिकल सेल डिसीज' है; जो सिकल सेल रोग से प्रभावित हर व्यक्ति तक समान, सुलभ एवं गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य सेवा पहुँचाने पर बल देती है। गुजरात पिछले दो दशकों से सिकल सेल रोग के शीघ्र निदान, प्रभावी उपचार, रोगी सहायता तथा जन जागृति के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है।

गुजरात 'सिकल सेल एनीमिया नियंत्रण कार्यक्रम' शुरू करने वाला पहला राज्य

वर्तमान प्रधानमंत्री तथा तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात में वर्ष 2006 में 14 आदिजाति जिलों में 'सिकल से एनीमिया नियंत्रण कार्यक्रम' की शुरुआत की गई थी। गुजरात यह कार्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना था। इस पहल के चलते आदिजाति समुदाय में सिकल सेल एनीमिया रोग के बारे में जागरूकता आई है और रोग को लेकर व्याप्त भ्रांतियाँ भी दूर हुई हैं। इस कार्यक्रम अंतर्गत अब तक राज्य के कुल 1.11 करोड़ से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग की गई है। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने सिकल सेल एनीमिया को लेकर जागृति, समय रहते निदान, उपचार तथा आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की है। राज्य सरकार ने सामूहिक स्क्रीनिंग कार्यक्रमों के अलावा; विवाह पूर्व जेनेटिक काउंसेलिंग तथा टेस्टिंग को भी प्रोत्साहन दिया है। पिछले पाँच वर्षों में 23,11,676 लोगों की स्क्रीनिंग की गई है, जो सिकल सेल रोग नियंत्रण के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दर्शाता है।

सिकल सेल रोगियों के लिए राज्य में निदान एवं उपचार की सुदृढ़ व्यवस्था

हाल में राज्य में 30,512 सिकल सेल रोगी दर्ज हैं। राज्य के 14 आदिजाति जिलों में इस रोग के निदान के लिए 41 एचपीएलसी/मिनी इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीनें कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त; वलसाड, नवसारी तथा डांग (रूमला) में 3 डे-केयर सेंटर्स कार्यरत हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर डीटीटी टेस्ट और सामूहिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं जिला अस्पतालों में एचपीएलसी/मिनी इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीनों द्वारा सिकल सेल का निदान किया जाता है, जबकि उपचार सुविधाएँ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों से लेकर जिला अस्पतालों तक उपलब्ध हैं।

रोगी सहाय योजना अंतर्गत कुल 18.15 करोड़ रुपए की सहायता का भुगतान किया गया

सिकल सेल मरीजों को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार ने रोगी सहायता योजना लागू की है। इस योजनांतर्गत अब तक आदिजाति क्षेत्रों के 13,040 सिकल सेल रोगियों को मासिक 2,500 रुपए के हिसाब से कुल 18.15 करोड़ रुपए की सहायता का भुगतान किया गया है। यह सहायता रोगियों को आजीवन दी जाती है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2024-25 से रोगी सहायता की मासिक राशि 500 रुपए से बढ़ाकर 2,500 रुपए की गई है।

काउंसेलिंग तथा जन जागृति से सिकल सेल के विरुद्ध लड़ाई मजबूत हुई

राज्य सरकार द्वारा घरेलू स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएँ और मार्गदर्शन पहुँचाने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर 180 काउंसेलरों की नियुक्ति की गई है। इन काउंसेलरों द्वारा सिकल सेल रोग के बारे में अधिक जागृति फैलाने और इस रोग को आगामी पीढ़ी तक फैलने से रोकने के उद्देश्य से काउंसेलिंग एवं कम्युनिटी आउटरिच कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। वर्ष 2025-26 के दौरान ऐसे कार्यक्रमों के तहत 1,57,432 लोगों को मार्गदर्शन तथा काउंसेलिंग सेवाएँ प्रदान की गई हैं।

स्कूल, कॉलेज, ग्राम सभा तथा समुदाय स्तर पर आयोजित जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा सिकल सेल रोग के लक्षणों, निदान एवं निवारण के विषय में लगातार जन जागरूकता फैलाई जा रही है। विशेषकर; युवाओं तथा नवदंपतियों में सिकल सेल स्क्रीनिंग के बारे में जागरूकता लाने पर विशेष बल दिया जा रहा है, जिससे आने वाली पीढ़ी को इस रोग से सुरक्षित रखा जा सके।

हाल में आयोजित 'सिकल सेल एनमीमिया-रोगी संवाद तथा मार्गदर्शन कार्यक्रम' में स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्री प्रफुल पानशेरिया ने विवाह से पूर्व परंपरागत कुंडली की तरह मेडिकल कुंडली का मिलान कराने यानी सिकल सेल स्टेटस की जाँच कराने पर बल दिया था।

सिकल सेल मुक्त भारत के संकल्प में गुजरात की उल्लेखनीय भूमिका

वर्ष 2010-11 में भारत सरकार की ओर से गुजरात राज्य को सिकल सेल एनीमिया रोग नियंत्रण क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए 'पीएम अवॉर्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन' से सम्मानित किया गया था। गुजरात के सिकल सेल नियंत्रण कार्यक्रम की सफलता को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने जुलाई 2023 से 'नेशनल सिकल सेल एलिमिनेशन मिशन-2047' प्रारंभ किया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2047 में भारत के अमृतकाल का उत्सव मनाने से पहले देश को सिकल सेल मुक्त बनाने का संकल्प किया है, जिसे साकार करने के लिए गुजरात सरकार निरंतर प्रयत्नशील है। राज्य में सिकल सेल नियंत्रण संबंधी सेवाओं को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए सूरत सिविल अस्पताल में आधुनिक निदान, अनुसंधान एवं काउंसेलिंग के लिए 'सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंस, रिसर्च एंड काउंसेलिंग' शुरू करने की दिशा में कार्य शुरू किया गया है।

वन्यजीवों की सुरक्षा हेतु भावनगर मंडल की महत्वपूर्ण पहल,एशियाई शेरों की सुरक्षित आवाजाही के लिए देश के प्रथम अंडरपास का निर्माण कार्य पूर्ण

पश्चिम रेलवे का भावनगर मंडल वन्यजीव संरक्षण एवं पर्यावरण सुरक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण एवं सराहनीय पहल को साकार कर रहा है। मंडल रेल प्रबंधक, भावनगर श्री दिनेश वर्मा के कुशल मार्गदर्शन में गिर एवं आसपास के संवेदनशील क्षेत्रों में एशियाई शेरों तथा अन्य वन्यजीवों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से देश के प्रथम अंडरपास का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

विश्व में एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास गिर एवं उसके आसपास का क्षेत्र है। इस अमूल्य वन्य धरोहर के संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए राज्य सरकार, वन विभाग एवं रेलवे प्रशासन के संयुक्त प्रयासों से ढसा–राजुला तथा राजुला–पीपावाव रेलखंड पर पाँच संवेदनशील स्थलों की पहचान की गई है, जहां वन्यजीवों की सुरक्षित आवाजाही के लिए विशेष अंडरपासों का निर्माण किया जा रहा है।

इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य शेरों एवं अन्य वन्यजीवों को रेलपथ पार करने के लिए सुरक्षित मार्ग उपलब्ध कराना तथा वन्यजीवों एवं रेल परिचालन दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए "शून्य दुर्घटना" (Zero Accident) के लक्ष्य को प्राप्त करना है।

लगभग 9.42 करोड़ रुपये की लागत से क्रियान्वित की जा रही इस परियोजना में अब तक उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है। ढसा–राजुला रेलखंड के किलोमीटर 53/14-15 एवं किलोमीटर 16/9-10 पर अंडरपास बॉक्स का निर्माण भी सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। शेष तीन स्थलों पर निर्माण कार्य तेजी से प्रगति पर है और निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा ने बताया कि भावनगर मंडल रेलवे परिचालन की सुरक्षा के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण एवं वन्यजीव सुरक्षा को भी समान रूप से प्राथमिकता दे रहा है। वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए विकसित की जा रही यह अभिनव पहल भारतीय रेलवे के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण है। रेलवे, वन विभाग एवं स्थानीय प्रशासन के समन्वित प्रयासों से यह परियोजना क्षेत्र में वन्यजीव संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर सिद्ध होगी।

पश्चिम रेलवे का भावनगर मंडल भविष्य में भी सुरक्षित, पर्यावरण-अनुकूल एवं सतत विकास को बढ़ावा देने वाली जनहितकारी तथा संरक्षणात्मक पहलों को निरंतर आगे बढ़ाता रहेगा।

नीट परीक्षा अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु भावनगर–गांधीग्राम के मध्य विशेष ट्रेन का संचालन,टिकटों की बुकिंग 19 जून, 2026 (शुक्रवार) से प्रारंभ होगी

यात्रियों तथा राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पश्चिम रेलवे द्वारा विशेष किराये पर भावनगर–गांधीग्राम–भावनगर के मध्य विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है।

भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि ट्रेन संख्या 09254 भावनगर टर्मिनस–गांधीग्राम स्पेशल दिनांक 20 जून, 2026 (शनिवार) को भावनगर टर्मिनस से 11:40 बजे प्रस्थान करेगी तथा भावनगर परा, सिहोर जंक्शन, धोला जंक्शन, बोटाद जंक्शन, धंधुका, धोलका, बावला एवं सरखेज स्टेशनों पर ठहराव लेते हुए 16:10 बजे गांधीग्राम पहुंचेगी।

इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09253 गांधीग्राम–भावनगर टर्मिनस स्पेशल दिनांक 21 जून, 2026 (रविवार) को गांधीग्राम से 20:00 बजे प्रस्थान करेगी तथा उपरोक्त स्टेशनों पर ठहराव लेते हुए रात्रि 00:35 बजे भावनगर टर्मिनस पहुंचेगी।

इस विशेष ट्रेन में यात्रियों की सुविधा के लिए कुल 24 कोच लगाए जाएंगे, जिनमें 20 सेकेंड क्लास स्लीपर कोच, 02 जनरल कोच तथा 02 एसएलआर/डी कोच शामिल होंगे।

ट्रेन नंबर 09254 और 09253 के लिए टिकटों की बुकिंग 19 जून, 2026 (शुक्रवार) से यात्री आरक्षण केंद्रों एवं आईआरसीटीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रारंभ होगी। यात्रीगण ट्रेन के समय, ठहराव एवं संरचना से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए भारतीय रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट www.enquiry.indianrail.gov.in पर अवलोकन कर सकते हैं।

मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा ने नीट परीक्षा अभ्यर्थियों एवं यात्रियों से अपील की है कि वे इस विशेष ट्रेन सेवा का अधिकतम लाभ उठाकर अपनी यात्रा को सुगम एवं सुविधाजनक बनाएं।

12 वर्ष : विकास के, जनविश्वास के और जनकल्याण के

मेट्रो रेल नेटवर्क : गुजरात के शहरों में आधुनिक सार्वजनिक परिवहन से बढ़ रही है ईज ऑफ लिविंग

गांधीनगर : सुबह के आठ बजे हैं। अहमदाबाद की व्यस्त सड़कों पर वाहनों की आवाजाही धीरे-धीरे बढ़ रही है। शहर अपनी रोजमर्रा की रफ्तार पकड़ रहा है। तभी मेट्रो ट्रेन में यात्रा के दौरान कोई समाचार पढ़ रहा है, कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, तो कोई अपने अगले काम की योजना बना रहा है। यह अहमदाबाद के सार्वजनिक परिवहन की बदली हुई तस्वीर है।

मेट्रो ट्रेन के परिणाम स्वरुप दैनिक रूप से यात्रा करने वाले नागरिकों के जीवन में कैसा परिवर्तन आया है, यह देखते हैं। मीडिया रिसर्चर के रुप में कार्यरत ऋचा के लिए मेट्रो आशीर्वादरूप बन गई है। अहमदाबाद से गांधीनगर अप-डाउन करने वाली ऋचा को एक समय गांधीनगर स्थित कार्यालय पहुंचने के लिए कई वाहन बदलने पड़ते थे। साथ ही, ट्रैफिक में उसका कीमती समय भी बर्बाद होता था। लेकिन अहमदाबाद-गांधीनगर के बीच मेट्रो ट्रेन शुरू होने के बाद उसका आवागमन अधिक आरामदायक हो गया है। आज वह मेट्रो की यात्रा के दौरान समाचार पढ़ती है, अपने क्षेत्र का शोध करती है और दिन की योजना भी बना लेती है। ऋचा कहती है, "मेट्रो ने मेरी यात्रा को सरल और सुरक्षित बना दिया है। मेट्रो की यात्रा के कारण मैं अपने समय का सदुपयोग कर पाती हूं।"

मेट्रो के आगमन के परिणामस्वरूप केवल ऋचा ही नहीं; बल्कि अनेक यात्रियों के लिए सार्वजनिक परिवहन अधिक आरामदायक तथा सस्ता बना है। मेट्रो के परिणामस्वरूप अहमदाबाद शहर के सार्वजनिक परिवहन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। मेट्रो के फेज-1 नेटवर्क से अहमदाबाद के स्थानीय व्यापारियों, विद्यार्थियों और दैनिक यात्रियों को लाभ हुआ है। साथ ही; इससे आश्रम रोड, सीजी रोड और पूर्वी क्षेत्रों में ट्रैफिक का भार कम हुआ है। फेज-1 नेटवर्क शहर के सबसे अधिक व्यस्त परिवहन केंद्रों को जोड़ता है।

मेट्रो फेज-2 के नेटवर्क के विस्तार से राज्य की आर्थिक राजधानी अहमदाबाद और राजनीतिक राजधानी गांधीनगर के बीच परिवहन अधिक सरल हुआ है। फेज-2 के कार्यरत होने से सचिवालय में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ गिफ्ट सिटी में कार्यरत आईटी प्रोफेशनल्स की यात्रा भी अधिक सुविधाजनक बनी है।

मेट्रो से बदली शहरी परिवहन की तस्वीर

आज भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क रखता है, जो आधुनिक शहरी परिवहन में उसकी प्रगति को दर्शाता है। मेट्रो नेटवर्क वर्ष 2014 में 248 किलोमीटर था, जो आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में बढ़कर 1,095 किलोमीटर तक पहुंच गया है। देश में मेट्रो कवरेज वाले शहरों की संख्या 5 थी, जो बढ़कर आज 26 हो गई है।

पर्यावरण संरक्षण के साथ प्रगति

भारत की मेट्रो रेल व्यवस्था में पर्यावरण का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। इसके अंतर्गत अधिकांश मेट्रो में 'रीजेनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम' का व्यापक उपयोग किया जा रहा है। यह टेक्नोलॉजी ट्रेन में ब्रेक लगाने के दौरान उत्पन्न होने वाली गतिज ऊर्जा को पुनः बिजली में परिवर्तित करती है। इस प्रकार; यह नूतन पहल बिजली की बचत करने के साथ-साथ कार्बन उत्सर्जन कम करने में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है।

गुजरात के मेट्रो परिवहन नेटवर्क में भी पर्यावरण अनुकूल इन्फ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। अहमदाबाद मेट्रो के चार भूमिगत स्टेशन; कांकरिया ईस्ट, कालुपुर, घीकांटा तथा शाहपुर को ग्रीन मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (एमआरटीएस) रेटिंग के अंतर्गत प्रतिष्ठित आईजीबीसी प्लेटिनम सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है; जो पर्यावरण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये प्रयास राज्य के सतत विकास के लक्ष्यों के साथ पूर्ण रूप से अनुरूप हैं और स्वच्छ शहरी परिवहन में मेट्रो की बढ़ती भूमिका को दर्शाती हैं।

मेट्रो एवं मेक इन इंडिया

भारत ने मेट्रो ट्रेन नेटवर्क में आधुनिकता के साथ आत्मनिर्भर भारत को भी प्राथमिकता दी है। 'मेक इन इंडिया' अभियान अंतर्गत सरकार ने कम-से-कम 75 प्रतिशत मेट्रो कोच तथा 25 प्रतिशत प्रमुख उपकरणों और उप-प्रणालियों की स्थानीय स्तर पर खरीद की व्यवस्था की है; जो स्थानीय उत्पादन को गति देने और परिवहन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

हाल ही में गुजरात सरकार ने 34 अत्याधुनिक मेट्रो ट्रेन सेटों का ऑर्डर दिया है, जिसमें अहमदाबाद मेट्रो फेज-2 के लिए 10 ट्रेन सेट तथा सूरत मेट्रो के लिए 24 ट्रेन सेट शामिल हैं। ये ट्रेनें कोलकाता स्थित टीटागढ़ की अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग फेसिलिटी में तैयार की जा रही हैं, जो हाई-टेक अर्बन मोबिलिटी सॉल्यूशंस के क्षेत्र में भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता को दर्शाती हैं।

भारत के वैश्विक व्यापार के लिए एक अहम मोड़: फियो अध्यक्ष श्री एस सी रल्हन

नई दिल्ली; 18 जून, 2026: ऐतिहासिक अमेरिका -ईरान समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर होना एक बड़ी कामयाबी है, जो वैश्विक व्यापार के तौर-तरीकों को बदलने का वादा करता है। भारतीय निर्यात- आयात समुदाय के लिए, यह घटनाक्रम मैक्रो-इकोनॉमिक राहत देने वाला है और कई महीनों की क्षेत्रीय रुकावटों के बाद ग्रोथ के लिए एक मज़बूत उत्प्रेरक का काम करेगा। पश्चिम एशिया में संघर्ष ने भारत के ट्रेड वॉल्यूम को कम कर दिया था, और सबसे ज़्यादा रुकावट के समय मिडिल ईस्ट को होने वाले निर्यात में भारी गिरावट आई थी। इस अस्थिरता का सबसे बुरा असर मुख्य सेक्टरों पर पड़ा। श्री रल्हन ने कहा कि लड़ाई खत्म होने और क्षेत्र के व्यापक आर्थिक एकीकरण के साथ, हमें उम्मीद है कि ऑर्डर बुक में तुरंत और ज़बरदस्त सुधार होगा। एक स्थिर वेस्ट एशिया रुकी हुई कंज्यूमर और इंडस्ट्रियल डिमांड को खोलता है, जिससे भारतीय निर्यातकों के लिए अपनी मौजूदगी बढ़ाने और आने वाली कुछ फाइनेंशियल तिमाहियों में शिपमेंट की रफ़्तार तेज़ करने का रास्ता बनता है। अपनी क्रूड ऑयल की ज़रूरतों का 85 प्रतिशत से ज़्यादा हिस्सा आयात करने वाले देश के तौर पर, ग्लोबल एनर्जी की कीमतें हमारी घरेलू मैन्युफैक्चरिंग लागत के ढांचे को तय करती हैं। क्षेत्रीय सप्लाई चेन पर खतरे ने पहले ब्रेंट क्रूड की कीमतों को ऊंचे स्तर पर पहुंचा दिया था, जिससे भारत में होलसेल महंगाई बढ़ गई थी। एमओयू के बाद, ब्रेंट क्रूड की कीमत में तेज़ी से सुधार हुआ है और यह 78 डॉलर प्रति बैरल के दायरे में आ गई है। फियो अध्यक्ष ने कहा कि जियोपॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम में इस कमी से सीधे तौर पर इंपोर्ट बिल कम होता है, फ्यूल से जुड़ी महंगाई घटती है, और प्लास्टिक, पेंट, टेक्सटाइल और केमिकल जैसे क्रूड पर बहुत ज़्यादा निर्भर निर्यात सेक्टरों के लिए इनपुट लागत में भारी कमी आती है, जिससे हमारी ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस बेहतर होती है।

एनर्जी की सप्लाई में आ रही रुकावट कम होने पर करेंसी मार्केट ने तुरंत सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। ऑयल रिफाइनर्स की तरफ से डॉलर की मांग में कमी और विदेशी पूंजी के मज़बूत प्रवाह ने भारतीय रुपये को मज़बूत आधार दिया है, जिससे यह डॉलर के मुकाबले 94–94.50 के स्तर तक मज़बूत हुआ है। निर्यातकों के लिए, एक स्थिर और अनुमान लगाने योग्य करेंसी सुरक्षित हेजिंग सुनिश्चित करती है, मार्जिन की रक्षा करती है, और उस अस्थिरता को खत्म करती है जिसने ऐतिहासिक रूप से लंबे समय के ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट्स को प्रभावित किया था। करंट अकाउंट डेफिसिट (सीएडी) पर कम दबाव पूरी अर्थव्यवस्था को राजकोषीय स्तर पर काम करने की ज़्यादा गुंजाइश देता है।

लॉजिस्टिक्स के नज़रिए से, यह एमओयू गेम-चेंजर है। होर्मुज़ जलडमरूमध्य का तुरंत फिर से खुलना—जहाँ से भारत का लगभग आधा कच्चा तेल आयात और कंटेनर ट्रैफिक का एक बड़ा हिस्सा गुज़रता है—ग्लोबल सप्लाई चेन के लिए सबसे बड़ी राहत है। अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी हटने और सामान्य ट्रैफिक बहाल होने से समुद्री रास्ते के लंबे चक्कर खत्म हो जाएंगे। इससे ईयू, अमेरिका और पश्चिम अफ्रीका को हमारा निर्यात काफी प्रतिस्पर्धी हो जाएगा। पहले निर्यातक बहुत ज़्यादा फ्रेट फीस और "युद्ध-जोखिम" इंश्योरेंस प्रीमियम के बोझ तले दबे हुए थे। हालात सामान्य होने से ये अतिरिक्त खर्च कम हो जाएंगे, जिससे पश्चिम एशिया और यूरोपीय जगहों तक वस्तुओं को पहुँचाना आसान, तेज़ और काफी सस्ता हो जाएगा।

फियो अध्यक्ष ने कहा कि हमने फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत बहुत सकारात्मक तरीके से की है, जिसमें शुरुआती दोनों महीनों में दोहरे अंकों में ग्रोथ हुई है। हालात और बेहतर होने के साथ, हम सरकार द्वारा घोषित 1 ट्रिलियन डॉलर के वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात का लक्ष्य हासिल करने की राह पर मज़बूती से आगे बढ़ रहे हैं।

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का राज्य स्तरीय उत्सव गांधीनगर जिले के माणसा में मनाया जाएगा : उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी

▸▸ योग दिवस पर राज्य में 1.25 करोड़ से अधिक नागरिक योग प्रोटोकॉल प्रशिक्षण में सहभागी होंगे

▸▸ राज्यभर में 14 जून से 20 जून तक मनाया जा रहा है 'योग सप्ताह' उत्सव

▸▸ 17 महानगर पालिकाओं, 33 जिलों की सभी तहसीलों, नगर पालिकाओं तथा ग्रामीण स्तर पर एक ही समय सामूहिक योगाभ्यास आयोजित होगा

▸▸ इस वर्ष की थीम 'योगा फॉर हेल्दी एजिंग' पर विशेष कार्यक्रम आयोजित होंगे

गांधीनग : 12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस उत्सव के विषय में विवरण देते हुए उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी ने कहा है कि समग्र देश में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सुशासन के 12 वर्ष का उत्सव विशिष्ट सेवाकीय कार्यों द्वारा मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत गुजरात में इस वर्ष 12वाँ अंतरराष्ट्रीय योग दिवस उत्साहपूर्वक मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में योग दिवस का राज्य स्तरीय उत्सव गांधीनगर जिले की माणसा तहसील में मनाया जाएगा, जिसमें 4 हजार से अधिक नागरिक सहभागी होंगे।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष 'योगा फॉर हेल्दी एजिंग' थीम पर विशेष कार्यक्रम आयोजित होंगे। इस संदर्भ में राज्य में अब तक 10 से अधिक बड़े कार्यक्रमों का सफल आयोजन हो चुका है। आगामी योग दिवस तक समग्र राज्य में स्कूलों, कॉलेजों, कॉर्पोरेट ऑफिसों, इंडस्ट्रीज, उद्यानों और सार्वजनिक मार्गों पर कुल मिलाकर लगभग 24,000 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है।

श्री संघवी ने जानकारी देते हुए जोड़ा कि इस वर्ष योग दिवस पर समग्र राज्य से 1.25 करोड़ से भी अधिक नागरिक योग प्रोटोकॉल प्रशिक्षण में भाग लेने वाले हैं। सभी जिलों में कलेक्टरों, महानगर पालिका आयुक्तों और सामाजिक संस्थाओं के समन्वय के साथ विभिन्न समितियाँ इस आयोजन को सफल बनाने के लिए कार्यरत हैं।

उन्होंने आगे कहा कि राज्य में 14 जून से 20 जून तक 'योग सप्ताह' मनाया जा रहा है। सफाई कर्मचारियों, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों तथा किसानों जैसे समाज के विभिन्न वर्गों को शामिल करके लगभग 12 विशेष कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इनमें से 10 कार्यक्रम संपन्न हो चुके हैं और शेष 2 कार्यक्रम आगामी दो दिनों में आयोजित होंगे। इसके अतिरिक्त; 17 महानगर पालिकाओं, 33 जिलों की सभी तहसीलों, नगर पालिकाओं और ग्रामीण स्तर पर एक ही समय सामूहिक योगाभ्यास आयोजित होगा। इस अनुसंधान में गुरुवार तड़के गांधीनगर स्थित गिफ्ट सिटी में 5,000 से अधिक सदस्यों ने उत्साहपूर्वक सहभागी होकर सामूहिक योग किया।

उप मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की विदेश यात्रा को याद करते हुए कहा कि विदेश की धरती पर विदेशी नागरिकों द्वारा योग के माध्यम से उनका स्वागत किया गया, जो दर्शाता है कि हमारी संस्कृति एवं योग आज दुनिया के कोने-कोने तक पहुँच गए हैं। भारत में ही नहीं, बल्कि विश्व में आज बहुत ही आकर्षक वेतन के साथ भारतीय योग शिक्षकों की मांग में वृद्धि हुई है।

सामान्य नागरिक प्रतिदिन सुबह योग कर सकें; इसके लिए गुजरात योग बोर्ड द्वारा प्रशिक्षण एवं सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं। उप मुख्यमंत्री ने इस सराहनीय कार्य के लिए योग बोर्ड के अध्यक्ष तथा उनकी समग्र टीम को अभिनंदन दिया।

पश्चिम रेल्वे

निर्माण कार्य

मंडल रेल प्रबंधक (WA), पश्चिम रेलवे, मुंबई सेंट्रल, मुंबई - 400 008. ई-निविदा अधिसूचना क्रमांक: BCT/26-27/71, दिनांक 15.06.2026 आमंत्रित करता है। कार्य और स्थान: पश्चिम रेलवे के उकाई सोनगढ - जलगांव मंडल के बीच SSE/W/अमलनेर के अधिकार क्षेत्र में अमलनेर में 20 बिस्तरों वाले आरपीएफ बैरक का निर्माण और स्टाफक्वार्टरों में आंगन, शौचालय, रसोई, छत और फर्श का सुधार। (विद्युत कार्य सहित संयुक्त निविदा)। कार्य की अनुमानित लागत: ₹4,80,76,993.39/- EMD: ₹9,61,500/-। जमा करने की तिथि और समय: दि.10.07.2026 को 15:00 बजे तक. खुलने की तिथि और समय: दि.10.07.2026 के 15:30 बजे तक. ज़्यादा जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.ireps.gov.in पर जाएं। मैन्युअल ऑफ़र पर विचार नहीं किया जाएगा। 0264

हमें लाईक करें: facebook.com/WesternRly

पश्चिम रेलवे – रतलाम मंडल

संख्या :- EL-2025-26-45R1, 4R & EL-2026-27-07 दिनांक: 17/06/2026

ई-टेंडरिंग नोटिस

मंडल रेल प्रबंधक (बिजली / पॉवर शाखा) पश्चिम रेलवे रतलाम की ओर से निम्नलिखित कार्य के लिए "खुली निविदा ई-निविदा के माध्यम से वेब-साईट **www.ireps.gov.in** पर आमंत्रित करते है। विवरण इस प्रकार है।

क्र. सं.: 1. ई-टेंडरिंग: EL-2025-26-45R1. कार्य का नाम: Ratlam Division - Upgradatior of station including circulating area, water supply and approach roads at Ujjain, Laxmibai nagar and Naikheri (Simhastha 2028). **अनुमानित लागत**: रु 1,03,20,570.13. **बयाना राशि**: रु 2,06,400/-. **कार्य समापन अवधि**: 12 Months. **क्र. सं.: 2. ई-टेंडरिंग: EL-2025-26-4R. कार्य का नाम**: Ratlam Division-Replacement & Repairing work of Pantry equipment's in LHB AC Pantry Car at IND and DADN based primary rakes for a period of two years. **अनुमानित लागत**: रु 98,79,257.26. **बयाना राशि**: रु 1,97,600/-. **कार्य समापन अवधि**: 24 Months. **क्र. सं.: 3. ई-टेंडरिंग: EL-2026-27-07. कार्य का नाम**: RRatlam Division - Electrical work in connection with raising of platforms at Pachwan (PF01), Parbati (PF01) and 04 meter wide Foot Over Bridge with 02 ramp landings at PNWN and PRB. **अनुमानित लागत**: रु 15,02,807.31. **बयाना राशि**: रु 30,100/-. **कार्य समापन अवधि**: 12 Months. **ऊपर के सभी टेंडर के लिए वेबसाईट पर अपलोड करने की तिथि**: 16.06.2026. **निविदा खुलने की तिथि**: 14.07.2026. विस्तृत निविदा सूचना, अहाता शर्ते एवं अन्य शर्ते वेबसाइट **www.ireps.gov.in** पर उपलब्ध है। टेंडर फॉर्म की कीमत NIL है। **AK/104**

हमें लाईक करें: facebook.com/WesternRly • हमें फॉलो करें: x.com/WesternRly

पश्चिम रेलवे
भावनगर मंडल

सिग्नलिंग उपकरणों की सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग,

भारत के राष्ट्रपति की ओर से और उनके लिए मंडल रेल प्रबंधक (S&T) पश्चिम रेलवे, भावनगर निम्नलिखित कार्यों के लिए ई-निविदाएं आमंत्रित करता हैं :- **निविदा क्रमांक :-** DRMSnT-BVP-Sig11of26-27 **कार्य का नाम:** भावनगर डिवीज़नः भीमनाथ में अतिरिक्त लूप लाइन बनाने के काम के सिलसिले में सिग्नलिंग उपकरणों की सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग, तथा मेधा (Medha) मेक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में बदलाव। **अनुमानित लागत :** रू 25757797.79/- (रुपये दो करोड़ सत्तावन लाख सत्तावन हजार सात सौ सत्तानवे और उनासी पैसे मात्र) बोली दाताओं को अधिक जानकारी के लिए केवल **www.ireps.gov.in** के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा. कृपया वेबसाइट **www.ireps.gov.in** पर जाएं. ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 09/07/2026 को 15.00 बजे तक रहेगी. **BVP 062**

हमें लाइक करें: facebook.com/WesternRly

पश्चिम रेल्वे द्वारा अहमदाबाद ⇌ पटना स्पेशल ट्रेन के फेरे बढाए जाएंगे

ट्रेन नं.	से	तक	चलाने के दिन	चलाने की तारीख
09447	अहमदाबाद	पटना	बुधवार	24.06.2026
09448	पटना	अहमदाबाद	शुक्रवार	26.06.2026

समय, ठहराव और संरचना के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए, यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जा सकते हैं।

ट्रेन नंबर 09447 की बुकिंग दि.19.06.2026 से सभी PRS काउंटरों और IRCTC वेबसाइट पर शुरू होगी। यह ट्रेन स्पेशल किराए के साथ स्पेशल ट्रेन के तौर पर चलाई जागेगी।

पश्चिम रेलवे
wr.indianrailways.gov.in

हमें लाइक और फॉलो करें:
facebook.com/WesternRly
X.com/WesternRly
Instagram.com/WesternRly
https://www.youtube.com/@WesternRly
https://bit.ly/WesternRailwayOfficial

कृपया सभी आरक्षित टिकटों के लिए मूल पहचान पत्र साथ रखें।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में अल नीनो की संभावित चुनौतियों से निपटने के लिए गुजरात का पूरा प्रशासनिक तंत्र तैयार : श्री जीतूभाई वाघाणी, प्रवक्ता मंत्री

▶▶ नर्मदा पाइपलाइन के 3 किमी के दायरे में आने वाले तालाबों को भरने की सीमा बढ़ाकर 7 किमी करने का मुख्यमंत्री का निर्णय, पेयजल के लिए राज्य के 300 तालाबों और सौराष्ट्र के विभिन्न बांधों को भरने का आदेश

▶▶ अल नीनो की चुनौतियों से निपटने के लिए कृषि, सिंचाई, जलापूर्ति, नर्मदा और राजस्व विभाग की समन्वित माइक्रो प्लानिंग

▶▶ पशुओं के लिए पर्याप्त चारे की व्यवस्था करने के आदेश, राज्य में अभी चारे का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है, जो वर्षों के लिए काफी है

▶▶ किसानों के लिए 'आकस्मिक फसल योजना' घोषित, एआई आधारित 'कृषि प्रगति पोर्टल' के जरिए 50 लाख से अधिक किसानों को मिलेगा मार्गदर्शन

गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने गुरुवार को गांधीनगर में अल नीनो के संभावित प्रभाव से निपटने के लिए राज्य की पूरी तैयारी की समीक्षा करने के लिए एक सर्वग्राही और उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। इस बैठक में कृषि मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी सहित कृषि, सिंचाई, जलापूर्ति, नर्मदा, वन और राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

इस महत्वपूर्ण बैठक के बाद जानकारी देते हुए प्रवक्ता मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी ने कहा कि भारतीय मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अल नीनो की संभावित परिस्थिति से निपटने के लिए नागरिकों, किसानों और पशुधन के हित के लिए राज्य सरकार के सभी विभाग मिलकर अग्रिम योजना के साथ काम कर रहे हैं।

प्रवक्ता मंत्री ने कहा कि बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य की मुख्य जीवनरेखा सरदार सरोवर नर्मदा बांध के अलावा राज्य के सभी क्षेत्रों के जलाशयों में संग्रहित पानी के भंडार की गहराई से समीक्षा की। राज्य में पेयजल की कोई किल्लत न हो, इसके लिए जल संसाधन और जलापूर्ति विभाग को नर्मदा नेटवर्क के साथ जोड़कर अग्रिम आयोजन करने का आदेश दिया गया है।

मुख्यमंत्री के आदेश के अनुसार सौराष्ट्र में पीने के पानी के बांध में जल्द ही सौराष्ट नर्मदा अवतरण सिंचाई योजना (सौनी योजना) के माध्यम से भरा जाएगा। मुख्यमंत्री ने बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय भी किया। पहले नर्मदा पाइपलाइन के 3 किलोमीटर के दायरे में आने वाले तालाब ही भरे जाते थे, लेकिन अब पाइपलाइन से 7 किलोमीटर के दायरे में आने वाले तालाब भी नर्मदा के पानी से भरे जाएंगे। इस निर्णय के अनुसार, मुख्यमंत्री ने सुजलाम सुफलाम योजना के जरिए उत्तर गुजरात के 300 से अधिक तालाबों को भरने का भी निर्देश दिया है।

कृषि क्षेत्र की तैयारियों को लेकर प्रवक्ता मंत्री ने कहा कि खरीफ-2026 सीजन के लिए राज्य में बीज और खाद का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। कृषि विभाग ने अल नीनो की संभावित परिस्थिति में किसानों को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए 'आकस्मिक फसल योजना' तैयार की है, जिसमें वैज्ञानिक सलाह और वैकल्पिक अल्पकालिक तथा कम पानी में उगने वाली फसलों की जानकारी किसानों के लिए उपलब्ध कराई गई है।

इसके अलावा, कृषि विभाग सैटेलाइट के जरिए जमीन की नमी और फसल की सेहत पर नजर रख रहा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) संचालित 'कृषि प्रगति' के माध्यम से 50 लाख से अधिक किसानों को सीधे उनके मोबाइल पर लाइव मौसम और कृषि सलाह के एसएमएस भेज रहा है।

किसानों के साथ-साथ राज्य के पशुधन की सुरक्षा भी सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। प्रवक्ता मंत्री ने कहा कि संभावित अल नीनो की स्थिति में पशुओं के लिए चारे की कमी न हो, इसके लिए वन विभाग और पशुपालन विभाग को पर्याप्त मात्रा में चारे की अग्रिम व्यवस्था और बफर स्टॉक तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं। अभी राज्य सरकार के पास चारे का बफर स्टॉक उपलब्ध है, जो दो वर्षों के लिए काफी है।

मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग को सभी जिला प्रशासनों और कलेक्टरों के साथ लगातार संपर्क में रहते हुए परिस्थिति पर चौबीसों घंटे, सातों दिन नजर रखने और पूरी तरह से सतर्क रहने को कहा है।

प्रवक्ता मंत्री ने कहा कि वर्ष 2000 से 2026 के दौरान राज्य में कुल 8 खरीफ अल नीनो वर्ष दर्ज किए गए हैं। अतीत के डेटा बताते हैं कि हर अल नीनो वर्ष कमजोर नहीं होता। वर्ष 2006 और 2023 में अत्यंत तीव्र अल नीनो होने के बावजूद गुजरात में 117 फीसदी बारिश दर्ज हुई थी। इसलिए, किसानों या जनता को चिंता करने या भ्रामक अफवाहों से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने नागरिकों से सरकार के निर्देशों का पालन करने को कहा।

प्रवक्ता मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री के सक्षम नेतृत्व में समूचा प्रशासनिक तंत्र, विभिन्न विभाग और कृषि यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक आपसी समन्वय के साथ लगातार कार्यरत हैं। राज्य सरकार की तैयारी मजबूत है और सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने को कटिबद्ध है।

बैठक में मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार श्री हसमुख अढिया, नर्मदा निगम के प्रबंध निदेशक श्री मुकेश पुरी, राजस्व विभाग की अपर मुख्य सचिव डॉ. जयंती रवि, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री संजीव कुमार, कृषि विभाग के प्रधान सचिव श्री आर.सी. मीणा, जलापूर्ति विभाग की प्रधान सचिव श्री शाहमीना हुसैन, मुख्यमंत्री के अपर प्रधान सचिव श्री विक्रांत पांडे, मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री एस.एस. राठौर सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।

तीन छात्रों की आत्महत्या, पेपर लीक और NEET पुनर्परीक्षा से पहले के तनाव को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। राजस्थान, उत्तराखंड और दिल्ली के तीन छात्रों ने कथित तौर पर NEET की पुनर्परीक्षा से पहले आत्महत्या कर ली। NEET-UG परीक्षा में प्रश्नपत्र लीक होने और अन्य अनियमितताओं के आरोपों के बाद NTA जांच और आलोचना का सामना कर रहा है। प्रश्नपत्र लीक होने के आरोपों के बाद 3 मई को होने वाली NEET 2026 परीक्षा रद्द कर दी गई थी। परीक्षा अब 21 जून को होगी। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, राजस्थान के मृतक की पहचान झुंझुन जिले के कारी गांव निवासी 22 वर्षीय उमेश माली के रूप में हुई है। सीकर पुलिस के मुताबिक, मई 2026 में होने वाली परीक्षा (जो अब रद्द कर दी गई है) उमेश का तीसरा प्रयास था। हालांकि उन्होंने पहले कोचिंग सेंटरों में पढ़ाई की थी, लेकिन अब वे घर पर ही परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने एक सुसाइड नोट लिखकर कहा, "मैं इस दुनिया को छोड़ रहा हूं, मुझे माफ कर दीजिए।" और फिर आत्महत्या कर ली। एक अन्य मामले में, 24 वर्षीय रिया कुमारी थापा, जो NEET परीक्षा से ठीक पहले तनाव के कारण उत्तराखंड के देहरादून स्थित अपने घर में फांसी पर लटकी हुई मिलीं। मरने से पहले उन्होंने एक भावुक नोट लिखकर कहा, "मम्मी, पापा, मैं आपसे प्यार करती हूं।" मृतका 1999 के कारगिल युद्ध के एक पूर्व सैनिक की बेटी थीं और पढ़ाई में बहुत होशियार थीं। उन्होंने 12वीं कक्षा में 97% अंक प्राप्त करके अपने स्कूल में टॉप किया था। वह 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET-UG) की पुनः परीक्षा की तैयारी कर रही थी। इसी बीच, कुछ दिन पहले दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के पालम कॉलोनी स्थित अपने घर में एक 17 वर्षीय छात्रा मृत पाई गई। पुलिस के अनुसार, मूल रूप से राजस्थान की रहने वाली यह छात्रा अपने परिवार के साथ दिल्ली में रहती थी। जांच के दौरान पुलिस को एक नोटबुक मिली, जिसमें हस्तलिखित एक नोट था। उसमें उसने अपने माता-पिता से माफी मांगते हुए लिखा था कि वह उनकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर सकी। इस प्रकार, NEET परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक होने के बाद, देश भर के विभिन्न राज्यों से कम से कम पांच छात्रों ने आत्महत्या कर ली है। इसके चलते ऐसे मामलों की कुल संख्या बढ़कर आठ हो गई है। इस तरह, छात्र प्रश्नपत्र लीक, परीक्षा में अनियमितताओं, बेरोजगारी और केंद्र सरकार द्वारा भारत के युवाओं के साथ किए जा रहे सुनियोजित "धोखे" के कारण आत्महत्या कर रहे हैं।

सूरत के नासिरनगर की झुग्गी बस्ती को ध्वस्त किए जाने से 125 परिवार बेघर हुए, जिम्मेदार अधिकारियों को हटाने की मांग की

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरतः सूरत शहर के वाडे रोड इलाके में स्थित 60 साल पुरानी 'नासिरनगर' झुग्गी बस्ती को बिना किसी पूर्व सूचना या कानूनी नोटिस के पुलिस बल का प्रयोग करते हुए अचानक ध्वस्त कर दिए जाने और 125 परिवारों को बेघर कर देने की घटना ने सूरत शहर की प्रतिष्ठा को देश-विदेश में गंभीर रूप से धूमिल किया है। इस अमानवीय और असंवैधानिक कृत्य के लिए सूरत नगर निगम के कर्मचारी संघ ने सूरत नगर निगम के अधिकारियों - कार्यकारी अभियंता सुजल प्रजापति, कार्यकारी अभियंता जयंग जीवन रामजीवाला और अभियंता अर्पण परमार दे - की तत्काल बर्खास्तगी की मांग की है। इन अधिकारियों ने पिछले नवंबर 2025 की आधी रात को सूरत नगर निगम में कार्यरत यूनियनों के कार्यालयों के ताले तोड़कर और उनके सामान को बाहर फेंककर कर्तव्य का घोर उल्लंघन किया है। उन्होंने यह कृत्य सूरत नगर निगम की उपायुक्त (प्रतिनियुक्ति) श्रीमती निधि सिवाच के अधिकार और समर्थन से किया है। ऐसा करके इन अधिकारियों ने कर्तव्य का घोर उल्लंघन किया है और इसी कारण आज अनेक लोग बेघर हैं। और उन्हें बहुत यातनाएं झेलनी पड़ रही हैं। अधिकारियों की यह अनुशासनहीनता किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जा सकती। शायद अगर नगर आयुक्त ने नवंबर महीने में इस संबंध में उचित कदम उठाए होते, तो आज यह घटना न घटी होती। सूरत नगर निगम कर्मचारी संघ के अध्यक्ष भाई लाल बी. वैष्णव, उपाध्यक्ष किरित सिंह वाघेला, महासचिव मोहम्मद इकबाल शेख और मंत्री हरीश राठौड़, जयंतीभाई वाघेला, शशिकांतभाई सोलंकी, विजयभाई शेनमेरे, देवेंद्र प्रजापति आदि ने कहा है कि सूरत नगर निगम में कानून का राज नहीं है और नगर निगम के अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, जिसकी कड़ी निंदा की जाती है। इन अधिकारियों की गलतियाँ अक्षम्य हैं। उन्होंने सूरत नगर निगम की प्रतिष्ठा को धूमिल किया है और देश-विदेश में इसकी छवि खराब की है। इसलिए, उन्होंने मांग की है कि उन्हें तत्काल आधार पर सूरत नगर निगम के पदों से मुक्त किया जाए।

VGRC सेंट्रल गुजरातः 210 देशों तक 1.74 लाख करोड़ रुपये के निर्यात के साथ सेन्ट्रल गुजरात ने बनाई नई वैश्विक पहचान

▶▶ 31,061 करोड़ रुपये के निर्यात के साथ फार्मास्यूटिकल्स बना सबसे बड़ा निर्यात क्षेत्र

▶▶ अहमदाबाद ने अकेले 97,752 करोड़ रुपये के निर्यात के साथ किया क्षेत्र का नेतृत्व

▶▶ सेन्ट्रल गुजरात के DMIC, DSIR और वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर से मिली औद्योगिक विकास को नई गति

▶▶ VGRC सेंट्रल गुजरात निवेश, नवाचार और वैश्विक साझेदारियों के नए अवसर खोलेगा

गांधीनगर : आगामी वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस (VGRC), सेंट्रल गुजरात का आयोजन 29 एवं 30 जून 2026 को वडोदरा स्थित GSFC यूनिवर्सिटी में होने जा रहा है। यह सम्मेलन ऐसे क्षेत्र की उपलब्धियों को सामने लाएगा, जिसने पिछले कुछ वर्षों में गुजरात के प्रमुख औद्योगिक और निर्यात केन्द्र के रूप में अपनी मजबूत पहचान बनाई है। इस प्रकार के क्षेत्रीय सम्मेलनों का उद्देश्य स्थानीय क्षमताओं को राष्ट्रीय एवं वैश्विक मंच प्रदान करना, क्षेत्र-विशिष्ट चुनौतियों के समाधान तलाशना तथा निवेश और विकास के नए अवसरों को बढ़ावा देना है। सेंट्रल गुजरात की यह बढ़ती औद्योगिक और आर्थिक ताकत उसके निर्यात प्रदर्शन में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है।

210 से अधिक देशों तक पहुंचा 1.74 लाख करोड़ रुपये का निर्यात

उल्लेखनीय है कि वित्त वर्ष 2024-25 में सेंट्रल गुजरात क्षेत्र से लगभग 1.74 लाख करोड़ रुपये मूल्य के उत्पादों का निर्यात किया गया। क्षेत्र के उत्पादों ने 210 से अधिक देशों में अपनी पहुंच बनाई, जो इसकी मजबूत औद्योगिक क्षमता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को दर्शाता है। इस अवधि में संयुक्त राज्य अमेरिका क्षेत्र का प्रमुख निर्यात गंतव्य रहा, जहां 41,346 करोड़ रुपये मूल्य के उत्पाद निर्यात किए गए।

फार्मास्यूटिकल्स बना निर्यात की रीढ़, 31 हजार करोड़ रुपये से अधिक का योगदान

सेंट्रल गुजरात के निर्यात में फार्मास्यूटिकल्स सेक्टर का सबसे बड़ा योगदान रहा। वित्त वर्ष 2024-25 में इस क्षेत्र से 31,061 करोड़ रुपये मूल्य के फार्मास्यूटिकल उत्पादों का निर्यात किया गया। इसके अलावा भारी मशीनरी एवं मैकेनिकल उपकरणों का 23,585 करोड़ रुपये, विद्युत मशीनरी एवं उपकरणों का 15,124 करोड़ रुपये, सड़क वाहनों एवं उनके पुर्जों का 12,418 करोड़ रुपये तथा ऑर्गेनिक केमिकल्स का 12,248 करोड़ रुपये मूल्य का निर्यात हुआ। रंगाई एवं टैनिंग उत्पाद, प्लास्टिक और उससे निर्मित वस्तुएं, लोहा एवं इस्पात उत्पाद, कपास तथा अनाज भी क्षेत्र के प्रमुख निर्यात उत्पादों में शामिल रहे।

अहमदाबाद रहा निर्यात का इंजन, वडोदरा और गांधीनगर ने भी दिखाई दमदार मौजूदगी

सेंट्रल गुजरात के कुल निर्यात में अहमदाबाद की हिस्सेदारी सबसे अधिक रही। जिले से 97,752 करोड़ रुपये मूल्य का निर्यात हुआ, जो क्षेत्र के कुल निर्यात का लगभग 56 प्रतिशत है। अहमदाबाद के निर्यात में भारी मशीनरी, फार्मास्यूटिकल्स और सड़क वाहनों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। वहीं वडोदरा से 41,765 करोड़ रुपये मूल्य के उत्पादों का निर्यात हुआ, जिसमें मैकेनिकल उपकरण और विद्युत मशीनरी प्रमुख रहे। गांधीनगर ने 13,366 करोड़ रुपये मूल्य के निर्यात के साथ प्लास्टिक उत्पादों, कपास तथा लोहा-इस्पात क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया।

सेन्ट्रल गुजरात के अंतर्गत विभिन्न जिलों की विविध उत्पाद क्षमता ने बनाई वैश्विक बाजारों में अलग पहचान

सेंट्रल गुजरात के विभिन्न जिलों ने अपनी विशिष्ट औद्योगिक क्षमताओं के माध्यम से निर्यात वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया। पंचमहल से फार्मास्यूटिकल्स और विद्युत उपकरणों का 11,707 करोड़ रुपये से अधिक का निर्यात हुआ। आणंद रंगाई एवं टैनिंग उत्पादों के लिए, खेड़ा प्लास्टिक उत्पादों और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए, जबकि नर्मदा फल, मेवे, फार्मास्यूटिकल्स तथा चीनी उत्पादों के निर्यात के लिए प्रमुख रहा।

इसी प्रकार महीसागर से फार्मास्यूटिकल्स और कॉस्मेटिक उत्पाद, दाहोद से मसाले और अनाज तथा छोटाउदेपुर से कपास एवं रासायनिक उत्पादों का उल्लेखनीय निर्यात किया गया। क्षेत्र की इस निर्यात सफलता के पीछे मजबूत औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र और विश्वस्तरीय अवसंरचना की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

DMIC, DSIR और फ्रेट कॉरिडोर से निर्यात एवं उद्योगों को मिली नई ताकत

सेन्ट्रल गुजरात की मजबूत लॉजिस्टिक्स और औद्योगिक अवसंरचना निर्यात वृद्धि की एक बड़ी आधारशिला बनकर उभरी है। गुजरात के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 62 प्रतिशत हिस्सा दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (DMIC) के प्रभाव क्षेत्र में आता है। इसके साथ ही ढोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन (DSIR) और मांडल-बेचाराजी SIR जैसे मेगा औद्योगिक प्रोजेक्ट्स उद्योगों को नई गति प्रदान कर रहे हैं। वहीं वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर अहमदाबाद, वडोदरा और आणंद को प्रमुख बंदरगाहों से सीधे जोड़कर निर्यातकों को तेज और कुशल परिवहन सुविधा उपलब्ध करा रहा है।

VGRC सेंट्रल गुजरात खोलेगा निवेश और वैश्विक साझेदारियों के नए द्वार

फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग, केमिकल्स, ऑटोमोबाइल, आईटी और वित्तीय सेवाओं जैसे क्षेत्रों में मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने के बाद अब सेंट्रल गुजरात सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, एयरोस्पेस एवं डिफेंस तथा ग्रीन एनर्जी जैसे उभरते क्षेत्रों में भी तेजी से अपनी पहचान बना रहा है।

ऐसे में आगामी VGRC सेंट्रल गुजरात क्षेत्र की औद्योगिक क्षमता, नवाचार और वैश्विक संभावनाओं को निवेशकों के समक्ष प्रस्तुत करने का एक महत्वपूर्ण मंच बनेगा। यह सम्मेलन नए निवेश, परियोजनाओं और अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों को प्रोत्साहित कर गुजरात की आर्थिक प्रगति को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति - एनईपी 2020 अंतर्गत

केन्द्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा 'स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग एसएचवीआर' 2025-26 में गुजरात के 15 विद्यालय राष्ट्रीय स्तर पर चमके

राष्ट्रीय स्तर पर चयनित राज्य के 15 विद्यालयों को प्रमाणपत्र तथा गतिविधियाँ बनाए रखने के लिए 1-1 लाख रुपए का फंड मिलेगा : श्री जे. रंजीत कुमार, निदेशक, राज्य परियोजना, समग्र शिक्षा अभियान, गुजरात

गांधीनगर : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी)-2020 के सफल पाँच वर्ष के उत्सव के भाग के रूप में देशभर में 'स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग - एसएचवीआर 2025-26' कार्यक्रम लॉन्च किया गया है, जिसमें गुजरात के 15 विद्यालयों का राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्रमाणपत्र के लिए अंतिम चयन किया गया है। इन विजेता विद्यालयों में राजकोट के तीन, वडोदरा, नवसारी व पोरबंदर के दो-दो तथा अहमदाबाद, आणंद, अरवल्ली, बनासकाँठा, वलसाड और मेहसाणा का एक-एक विद्यालय शामिल हैं।

समग्र शिक्षा अभियान-गुजरात के राज्य परियोजना निदेशक श्री जे. रंजीत कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर विजेता बने इन 15 विद्यालयों को भारत सरकार की ओर से विशेष प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त; विद्यालयों में ग्रीन तथा सस्टेनेबल-टिकाऊ गतिविधियों का क्रियान्वयन निरंतर जारी रहे एवं भविष्य के प्रयास बने रहें; इस उद्देश्य से प्रत्येक विद्यालय को 1 लाख रुपए का विशेष फंड भी राष्ट्रीय स्तर से प्रदान किया जाएगा।

उन्होंने और जानकारी देते हुए कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यालयों को स्वच्छ, हरित, सर्वसमावेशी, सुरक्षित एवं टिकाऊ शैक्षणिक वातावरण प्रदान करना है। एनईपी-2020 अंतर्गत विद्यार्थियों तथा विद्यालयों में व्यावहारिक परिवर्तन, पर्यावरणीय स्थिरता एवं क्लाइमेट रेजिलियन्स लाने के उद्देश्य से विद्यालयों का यह मूल्यांकन किया गया।

उन्होंने जोड़ा कि विद्यालयों में पानी, शौचालय, साबुन से हाथ धोना - हैंडवॉश, संचालन एवं रखरखाव ऑपरेशन - मैंटेनेंस, व्यवहार परिवर्तन तथा सशक्तिकरण - बिहेवियर चेंज - कैपेसिटी बिल्डिंग तथा 'मिशन लाइफ' अंतर्गत ऊर्जा संरक्षण एनर्जी कन्जर्वेशन, रिसाइकलिंग और इकोक्लब जैसी गतिविधियों के मानदंडों के आधार पर विद्यालयों की जाँच की गई।

श्री कुमार ने आगे कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के सक्षम मार्गदर्शन में तथा शिक्षा मंत्री श्री प्रद्युमन वाजा एवं शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती रिवाबा जाडेजा के नेतृत्व में राज्य के सभी सरकारी, अनुदानित और निजी मिलाकर कुल 44 हजार से अधिक विद्यालयों ने रिकॉर्डब्रेक और सफल पंजीकरण कर स्व-मूल्यांकन किया।

इस मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में 7 अन्य सदस्य और 1 सदस्य सचिव मिलाकर कुल 9 सदस्यों की समिति का गठन किया गया था। इसके अतिरिक्त; राज्य परियोजना निदेशक की अध्यक्षता में 14 अन्य सदस्य एवं 1 सदस्य सचिव मिलाकर कुल 16 सदस्यों की समिति द्वारा सूक्ष्मतापूर्ण क्रॉस वेरिफिकेशन किया गया।

नियमों तथा मानदंडों के अनुसार किए गए क्रॉस वेरिफिकेशन के अंत में जिला स्तर से कुल 262 विद्यालयों का चयन किया गया; जबकि राज्य स्तर पर अहमदाबाद, आणंद, अरवल्ली, बनासकाँठा, मेहसाणा, नवसारी, पाटण, पोरबंदर, राजकोट, सूरत, सुरेन्द्रनगर, वडोदरा व वलसाड जिलों का समावेश करते हुए कुल 20 श्रेष्ठ विद्यालयों का चयन किया गया। इनमें से 15 विद्यालयों का राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणपत्र के लिए अंतिम चयन किया गया।

19 जून : विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस

सिकल सेल जागरूकता के लिए गुजरात मॉडल की तर्ज पर देशभर में जुलाई 2023 में केंद्र सरकार ने 'राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन' की शुरुआत की : पद्मश्री डॉ. यज्दी इटालिया

▶▶ सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन द्वारा रोगियों को निःशुल्क जांच, निदान, उपचार, रक्त चढ़ाने जैसी विभिन्न चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध

▶▶ 'सिकल सेल रोग में जीवन रक्षा की असमानता को दूर कर समान स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करना' थीम पर इस वर्ष विभिन्न स्वरूपों में आयोजन

गांधीनगर : विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस के अवसर पर अग्रणी ट्रांसलेशनल वैज्ञानिक, पद्म श्री पुरस्कार विजेता और सिकल सेल नियंत्रण कार्यक्रम के आधारस्तंभ डॉ. यज्दी इटालिया ने भारत में सिकल सेल रोग (सिकल सेल रोग– एससीडी) के विरुद्ध लड़ाई में हुई उल्लेखनीय प्रगति को रेखांकित किया। उन्होंने साथ ही अधिक जागरूकता, समान स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और आधुनिक निवारक टेक्नोलॉजी के व्यापक क्रियान्वयन की आवश्यकता पर बल दिया।

सिकल सेल रोग विश्व में सबसे सामान्य आनुवांशिक रक्त रोगों में से एक है। भारत में विशेष रूप से आदिवासी समाज में इसका प्रसार अधिक देखा जाता है। वर्षों तक जागरूकता की कमी, देर से निदान और विशेष उपचार के अभाव के कारण हजारों मरीज अनावश्यक पीड़ा और गंभीर जटिलताओं का भोग बनते हैं। गुजरात ने वर्ष 2006 में तत्कालीन मुख्यमंत्री तथा वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में व्यापक सिकल सेल नियंत्रण कार्यक्रम शुरू कर देश में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर स्थापित किया है। इस कार्यक्रम अंतर्गत गांवों तथा आदिवासी क्षेत्रों में निःशुल्क स्क्रीनिंग, शीघ्र निदान, आनुवंशिक एवं नैतिक परामर्श, टीकाकरण, फोलिक एसिड और हाइड्रॉक्सीयूरिया जैसी दवाओं की उपलब्धता तथा नियमित फॉलो-अप सेवाएं शुरू की गई।

डॉ. इटालिया के अनुसार; गुजरात मॉडल ने स्वास्थ्य सेवाओं को आदिवासी समाज के घर-घर तक पहुंचाकर मरीजों में दर्द के दौरे, जटिलताओं और अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता में उल्लेखनीय कमी आई। इस मॉडल की सफलता को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा इसे देशभर में अपनाया गया और इसके बाद 1 जुलाई 2023 को भारत सरकार ने 'राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन' की शुरुआत की। इस मिशन का उद्देश्य वर्ष 2047 तक सिकल सेल रोग के बोझ को उल्लेखनीय रूप से कम करना है।

इस वर्ष का वैश्विक विषय है : क्लोजिंग द सर्वाईवल गैप : ''इक्विटी इन सिकल सेल डिसिज'' यानी "सिकल सेल रोग में जीवन रक्षा की असमानता को दूर कर समान स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करना।" यह विषय इस बात पर बल देता है कि विश्वभर के मरीजों को उनके भौगोलिक स्थान, आर्थिक स्थिति या सामाजिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना समय पर निदान, उपचार और दीर्घकालिक देखभाल प्राप्त हो।

सिकल सेल रोग गंभीर दर्द के दौरे, क्रोनिक एनीमिया, बार-बार होने वाले संक्रमण, महत्वपूर्ण अंगों को नुकसान और असामयिक मृत्यु जैसी गंभीर समस्याओं का कारण बन सकता है। डिहाइड्रेशन, संक्रमण, शारीरिक तनाव और अत्यधिक तापमान परिवर्तन इन जटिलताओं को बढ़ा सकते हैं। हालांकि विशेषज्ञों के अनुसार नियमित चिकित्सकीय निगरानी, टीकाकरण, पर्याप्त पानी पीना, समय पर उपचार और मरीजों की शिक्षा के माध्यम से इन जटिलताओं में से कई को रोका जा सकता है।

भारत सरकार ने आयुष्मान भारत योजना तथा राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन द्वारा मरीजों को विशेष सहायता प्रदान की है। इन योजनाओं के अंतर्गत निःशुल्क जांच, निदान, उपचार, रक्त चढ़ाने की सुविधा, 108 एम्बुलेंस सेवा तथा विभिन्न जटिलताओं का उपचार उपलब्ध कराया गया है। अनेक मरीज दिव्यांगता लाभों और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए भी पात्र बनते हैं।

डॉ. इटालिया ने कहा कि जागरूकता इस पूरे अभियान की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण आधारस्तंभ है। उन्होंने मरीजों और उनके परिवारजनों से स्वास्थ्यकर्मियों तथा सिकल सेल काउंसलरों के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखने, नियमित अनुसरण कराने और सरकार द्वारा उपलब्ध सभी सेवाओं का पूरा लाभ लेने की अपील की।

भविष्य की ओर देखते हुए विशेषज्ञों का मानना है कि अब रोकथाम को और अधिक केंद्र में लाने की आवश्यकता है। इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन (आईवीएफ) और प्री-इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस (पीजीडी) जैसी आधुनिक प्रजनन टेक्नोलॉजी उच्च जोखिम वाले दंपतियों को गंभीर आनुवंशिक रक्त रोगों से मुक्त स्वस्थ संतान प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती हैं। यदि ये तकनीकें अधिक सुलभ और किफायती बनती हैं, तो भविष्य में सिकल सेल रोग और थैलेसीमिया के बोझ में उल्लेखनीय कमी संभव हो सकती है।

इस क्षेत्र में अनुसंधान भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। नई दवाओं के विकास के साथ-साथ स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन और जीन एडिटिंग जैसी उन्नत उपचार पद्धतियां मरीजों के लिए नई आशा की किरण बन रही हैं।

राष्ट्रीय कार्यक्रम के ताजा आंकड़े दर्शाते हैं कि देश के सिकल सेल प्रभावित राज्यों में अब तक 7 करोड़ से अधिक लोगों की जांच की जा चुकी है। इनमें 2.46 लाख से अधिक सिकल सेल रोगग्रस्त मरीजों और 20 लाख से अधिक सिकल सेल ट्रेट वाले व्यक्तियों की पहचान हुई है। ये आंकड़े समस्या की व्यापकता को दर्शाते हैं और निरंतर स्क्रीनिंग, काउंसलिंग तथा उपचार की आवश्यकता पर बल देते हैं।

डॉ. इटालिया ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, नीति-निर्माताओं, आईएएस अधिकारियों, आईसीएमआर के वैज्ञानिकों, गुजरात ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्वास्थ्यकर्मियों, सिकल सेल काउंसलरों, सामाजिक संस्थाओं तथा सबसे महत्वपूर्ण मरीजों और उनके परिवारों के योगदान की सराहना की।

भारत सिकल सेल रोग को एक बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अंतिम लक्ष्य केवल उपचार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक बच्चे को स्वस्थ जीवन का अधिकार मिले, प्रत्येक मरीज को समय पर और संवेदनापूर्ण उपचार प्राप्त हो तथा प्रत्येक परिवार आशा और गौरव के साथ भविष्य की ओर देख सके।

पश्चिम रेलवे नीट परीक्षा के लिए चलाएगी पाँच जोड़ी स्पेशल ट्रेनें

पश्चिम रेलवे द्वारा राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) 2026 में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा तथा यात्रियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए विभिन्न गंतव्यों के बीच विशेष किराये पर पाँच जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इन स्पेशल ट्रेनों का परिचालन नीट परीक्षा के लिए यात्रा करने वाले यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को सुगमता से नियंत्रित करने के उद्देश्य से किया जाएगा। इन ट्रेनों का विवरण निम्नानुसार है:

1. ट्रेन संख्या 09351/09352 बांद्रा टर्मिनस – डॉ. अम्बेडकर नगर स्पेशल

ट्रेन संख्या 09351 बांद्रा टर्मिनस – डॉ. अम्बेडकर नगर स्पेशल शनिवार, 20 जून, 2026 को बांद्रा टर्मिनस से 18:20 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन 11:30 बजे डॉ. अम्बेडकर नगर पहुँचेगी। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09352 डॉ. अम्बेडकर नगर – बांद्रा टर्मिनस स्पेशल शुक्रवार, 19 जून, 2026 को डॉ. अम्बेडकर नगर से 23:00 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 15:40 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुँचेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, पालघर, वापी, वलसाड, बिलीमोरा, नवसारी, सूरत, अंकलेश्वर, भरूच, छायापुरी, गोधरा, दाहोद, रतलाम, उज्जैन तथा इंदौर स्टेशनों पर ठहरेगी।

इस ट्रेन में स्लीपर क्लास तथा द्वितीय श्रेणी के सामान्य कोच होंगे।

2. ट्रेन संख्या 09471/09472 बांद्रा टर्मिनस – मणिनगर स्पेशल

ट्रेन संख्या 09471 बांद्रा टर्मिनस – मणिनगर स्पेशल शनिवार, 20 जून, 2026 को बांद्रा टर्मिनस से 21:15 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन 06:00 बजे मणिनगर पहुँचेगी। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09472 मणिनगर – बांद्रा टर्मिनस स्पेशल शनिवार, 20 जून, 2026 को मणिनगर से 08:30 बजे प्रस्थान करेगी और उसी दिन 18:15 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुँचेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, पालघर, वापी, वलसाड, नवसारी, सूरत, भरूच, विश्वामित्री तथा आणंद स्टेशनों पर ठहरेगी।

इस ट्रेन में स्लीपर क्लास तथा द्वितीय श्रेणी के सामान्य कोच होंगे।

3. ट्रेन संख्या 09554/09553 ओखा – गांधीनगर केपिटल स्पेशल

ट्रेन संख्या 09554 ओखा – गांधीनगर केपिटल स्पेशल शनिवार, 20 जून, 2026 को ओखा से 05:00 बजे प्रस्थान करेगी तथा उसी दिन 15:00 बजे गांधीनगर केपिटल पहुँचेगी। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09553 गांधीनगर केपिटल – ओखा स्पेशल रविवार, 21 जून, 2026 को गांधीनगर केपिटल से 20:55 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 06:40 बजे ओखा पहुँचेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में द्वारका, भाटिया, खंभालिया, कानालुस, जामनगर, हापा, पडधरी, राजकोट, वांकानेर, थान, मूली रोड, सुरेंद्रनगर, विरमगाम, आंबली रोड तथा चांदलोडिया स्टेशनों पर ठहरेगी।

इस ट्रेन में स्लीपर क्लास तथा द्वितीय श्रेणी के सामान्य कोच होंगे।

4. ट्रेन संख्या 09254/09253 भावनगर – गांधीग्राम स्पेशल

ट्रेन संख्या 09254 भावनगर – गांधीग्राम स्पेशल शनिवार, 20 जून, 2026 को भावनगर से 11:40 बजे प्रस्थान करेगी तथा उसी दिन 16:10 बजे गांधीग्राम पहुँचेगी। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09253 गांधीग्राम – भावनगर स्पेशल रविवार, 21 जून, 2026 को गांधीग्राम से 20:00 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 00:35 बजे भावनगर पहुँचेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में भावनगर परा, सिहोर, धोला जं., बोटाद, धंधुका, ढोलका, बावला तथा सरखेज स्टेशनों पर ठहरेगी।

इस ट्रेन में स्लीपर क्लास तथा द्वितीय श्रेणी के सामान्य कोच होंगे।

5. ट्रेन संख्या 09354/09353 इंदौर – भोपाल – रतलाम स्पेशल

ट्रेन संख्या 09354 इंदौर – भोपाल स्पेशल शनिवार, 20 जून, 2026 को इंदौर से 11:25 बजे प्रस्थान करेगी तथा उसी दिन 19:00 बजे भोपाल पहुँचेगी। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09353 भोपाल – रतलाम स्पेशल शनिवार, 20 जून, 2026 को भोपाल से 19:40 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 00:55 बजे रतलाम पहुँचेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में रतलाम, नागदा, उज्जैन, मक्सी, शुजालपुर, सीहोर तथा संत हिरदाराम नगर स्टेशनों पर ठहरेगी।

ट्रेन संख्या 09354 में फतेहाबाद चंद्रावतीगंज तथा बड़नगर स्टेशनों पर अतिरिक्त ठहराव होगा।

इस ट्रेन में स्लीपर क्लास तथा द्वितीय श्रेणी के सामान्य कोच होंगे।

ट्रेन संख्या 09351, 09352, 09471, 09472, 09554, 09553, 09254, 09253 तथा 09354 की बुकिंग 19.06.2026 से सभी पीआरएस काउंटरों तथा आईआरसीटीसी वेबसाइट पर शुरू होगी। ट्रेनों के ठहराव, समय तथा संरचना की विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।